PERFECT 7

FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

जून 2022 / Issue - 1

यूपीएससी और राज्य आधारित पीसीएस परीक्षाओं के लिए उपयोगी

- वर्तमान संदर्भ में जलवायु परिवर्तन में संबंधित वित्तीय असमानता
- खाद्य तेल संकट : कारण, प्रभाव और समाधान
- वर्तमान परिदृश्य में राजद्रोह कानून की प्रासंगिकता
- भारत और दुनिया पर श्रीलंका के आर्थिक संकट का प्रभाव
- फार्मास्यूटिकल नवाचार तथा उद्यमिता
- बुल्डोजर न्याय
- मुफ्त की राजनीति

dhyeyaias.com

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PMI

(PRE+MAINS+INTERVIEW) PROGRAMME 2022

JUNE 2022 SCHEDULE

19th June — **PRELIMS**

26th June — **MAINS**

3rd July — **INTERVIEW**

Personality Test by a Panel of Retd. & Working Bureaucrats and Professors

SYLLABUS
PRELIMS & MAINS

(TOPIC : Geography & Environment, Current of February 2022)

Source :
NCERT-6th to 10th (Dhyeya Class Notes + Magazine Perfect-7 + Open Sources)

SYLLABUS
ESSAY

(TOPIC : Effects of globalization on Indian society, Social empowerment, communalisms, regionalism & secularism, Ethics and Human Interface, Human Values)

Source : Open source, Dhyeya booklet

0522-4025825
9506256789

A-12 Sector-J Aliganj, Lucknow

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

20 वर्षों का भरोसा

सफलता ही हमारी परम्परा!

Hearty Congratulations!

FOR YOUR GRAND SUCCESS IN CSE 2021

Your sincere efforts made us proud

ARPIT GUPTA
AIR 54

NIKHIL MAHAJAN
AIR 80

CHARU DHANKAR
AIR 103

VIVEK TIWARI
AIR 164

KARMVEER KESHAV
AIR 170

ANAND KUMAR SINGH
AIR 206

SAURYA MAN PATEL
AIR 281

PREKSHA AGRAWAL
AIR 303

ANURAG NAYAN
AIR 379

CHAITANYA
AIR 397

RAJENDRA CHAUDHARY
AIR 514

RAVINDRA KUMAR MEENA
AIR 576

GAGAN SINGH MEENA
AIR 592

RAJESH KUMAR MEENA
AIR 622

& Many More....

Visit Website

Director's Message

Mr. Vinay Kumar Singh

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।
सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

Yours very truly,

Vinay Kumar Singh
CEO and Founder

Mr Q H Khan

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहां छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Yours very truly,

Q H Khan
Managing Director

प्रस्तावना

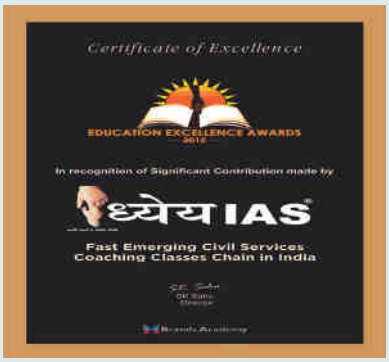

समसामयिक मुद्दे अथवा करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट 7 मैगजीन को विद्यार्थी जगत के समक्ष माह में दो बार रखा जा रहा है. आईएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के तथ्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाय. परफेक्ट 7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कंटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है. इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ साथ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है. एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, पेपर 4 के लिए एथिक्स की केस स्टडीज को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्वों के जीवन और भूमिक. ाओं, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर एक माह के 14 सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें सर्वाधिक जोर पर्यावरण पारिस्थितिकी, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी , अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर है. शब्दावली और अन्य आयामों एक छोटा खंड भी परफेक्ट 7 मैगजीन का पार्ट होगा.

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ाने के लिए ब्रेन बूस्टर्स को 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैश्विक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहेगी. इस मैगजीन को केवल तथ्यों या केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नही बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का विजन यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें. हमें उम्मीद हैं कि परफेक्ट 7 अपने नए रूप में आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा और इसके साथ ही आप सभी के सुझावों का स्वागत रहेगा.

विनय कुमार सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7 TEAM

संपादक · विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक · क्यू. एच. खान
सहसंपादक · गौतम तिवारी
उप-संपादक · आशुतोष मिश्र
· सौरभ चक्रवर्ती
सहायक उप-संपादक · अमन कुमार
प्रकाशन प्रबंधक · डॉ.एस.एम.खालिद
संपादकीय सहयोग · प्रिंस, गौरव चौधरी, देवेंद्र सिंह, लोकेश शुक्ल
मुख्य लेखक · विवेक ओझा
सहायक लेखक · मृत्युंजय त्रिपाठी,
मुख्य समीक्षक · ए.के श्रीवास्तव
· विनीत अनुराग
· बाघेन्द्र सिंह
आवरण सज्जा एवं विकास · प्रगति केसरवानी
· पुनीष जैन
टंकण · सचिन
· तरून
कार्यालय सहायक · राजू, चन्दन, अरुण

साभार : PIB, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, दैनिक जागरण, डाउन टू अर्थ, इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीक्ली, योजना, कुरुक्षेत्र, द प्रिंट

DHYEYA EDUCATIONAL SERVICES PVT. LTD.
AN ISO 9001:2008 COMPANY

Face to Face Centres

MUKHERJEE NAGAR : 9205274741, 9205274742
RAJENDRA NAGAR : 9205274743
LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002
ALLAHABAD : 0532-2260189, 8853467068
LUCKNOW (ALIGANJ) : 0522-4025825, 9506256789
LUCKNOW (GOMTINAGAR) : 7234000501, 7234000502
GREATER NOIDA : 9205336037, 9205336038
KANPUR : 7887003962, 7897003962
BHUBANESWAR : 8599071555
SRINAGAR (J&K) : 9205962002

PERFECT 7

FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

विषय सूची

समसामयिक लेख ---------- 1-14

- भारत में रोजगार परिदृश्य
- जर्मनी-भारत अंतर सरकारी परामर्श
- भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग- चुनौतियां और अवसर
- भारत में वनाग्नि और वनवासी समुदाय
- भारत में पेट्रोलियम तेल के दाम में हो रही वृद्धि और मुद्रास्फीति
- वैश्विक राजनीति के केंद्र में भारत
- न्यायपालिका तथा कार्यपालिका में टकराव

संक्षिप्त मुद्दे राष्ट्रीय ---------- : 15-16
संक्षिप्त मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय ---------- : 16-18
संक्षिप्त मुद्दे पर्यावरण ---------- : 18-20
संक्षिप्त मुद्दे विज्ञान एवं तकनीक ---------- : 20-21
संक्षिप्त मुद्दे आर्थिक ---------- 21-23
राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें ---------- 24-27
समसामयिक घटनाएं एक नजर में ---------- 28
ब्रेन बूस्टर ---------- 29-35
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा समसामयिक ---------- 36-38
बहुविकल्पीय प्रश्न ---------- 39-40
GS Paper IV के लिए हल केस स्टडी ---------- 41
व्यक्ति विशेष ---------- 42
इतिहास विषय की शब्दावलियां ---------- 43

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

वर्तमान संदर्भ में जलवायु परिवर्तन से संबंधित वित्तीय असमानता

परिचय

अगस्त 2021 की एक रिपोर्ट में, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ने यह निष्कर्ष निकाला कि पेरिस समझौते के जलवायु लक्ष्य जल्द ही तत्काल और बड़े पैमाने पर ग्रीनहाउस गैस के बिना, पहुंच से बाहर हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी कि यह रिपोर्ट ''मानवता के लिए एक कोड रेड है।'' जलवायु परिवर्तन और आर्थिक असमानता को अक्सर अलग-अलग मुद्दों के रूप में माना जाता है। हालांकि, इन मुद्दों में से एक को संबोधित किए बिना दूसरे को संबोधित करना असंभव है, क्योंकि वे जटिल रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से मानव जनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन नगण्य स्तर से बढ़कर प्रति वर्ष 40 बिलियन टन से अधिक हो गया है।हमारे वातावरण में जमा हो रहे इन उत्सर्जन के परिणामस्वरूप, पूर्व-औद्योगिक काल से औसत वार्षिक तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। ग्लेशियर और बर्फ की टोपियां पिघल गई हैं, समुद्र का स्तर बढ़ गया है, और अधिक लगातार और तीव्र मौसम की घटनाएं, जैसे ताप की लहरें और सूखा, बढ़ते तापमान के परिणामस्वरूप, पारिस्थितिक तंत्र, कृषि उत्पादन, मानव स्वास्थ्य और आजीविका पर व्यापक परिणामों के साथ दिखाई दे रहा है।

वित्तीय असमानता और जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन गरीबी में कमी के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है, जिससे दशकों की प्रगति बाधित होने का खतरा है। यद्यपि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक घटना है, गरीब लोग और राष्ट्र इसके विनाशकारी प्रभावों से पीड़ित हैं।विश्व की जनसंख्या का सबसे अमीर 1% प्रति वर्ष न्यूनतम 50% की तुलना में 100 गुना अधिक CO2 उत्सर्जित करता है। थॉमस पिकेटी और लुकास चांसल के एक अध्ययन के अनुसार, सबसे अमीर 10% व्यक्तिगत उत्स. र्जक वैश्विक उत्सर्जन में 45% का योगदान करते है।दुनिया के सबसे गरीब 50% दुनिया के कुल उत्सर्जन का लगभग 13% हिस्सा बनाते हैं। कनाडा के प्रति व्यक्ति वार्षिक कार्बन उत्स. र्जन, सबसे अमीर देशों में से एक के नागरिक, विश्व औसत का 35 गुना था, जो कनाडा को कार्बन उत्सर्जक स्तरों पर पांचवें स्थान पर रखता था। 2015 ऑक्सफैम अध्ययन के अनुसार, व्यक्तिगत स्तर पर, सबसे अमीर 10% खपत से सभी ब्व2 उत्सर्जन का लगभग आधा उत्पन्न करते हैं।ऑक्सफैम के शोध से यह भी पता चलता है कि सबसे धनी अमेरिकियों की जीवन शैली सबसे अमीर चीनी की तुलना में 10 गुना अधिक उत्सर्जन-गहन है।

कैसे असमानताएं जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं

- जब कोई सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यवहारों की नकल करने की कोशिश करता है तो उपभोग में असमानता कार्बन-गहन आदतों के निर्माण को प्रोत्साहित करती है।
- जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है
- वैश्विक CO2 उत्सर्जन के लगभग 8% के लिए पर्यटन जिम्मेदार है, और इस क्षेत्र की वृद्धि इसके प्रभावों को कम करने के सभी प्रयासों को पीछे छोड़ चुका है।
- असमानता सामाजिक एकता को नष्ट करती है और सामूहिक कार्रवाई में शामिल होने की व्यक्तिगत इच्छा को कमजोर करती है। यह सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को कमजोर करता है
- मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार, जब आय शीर्ष पर केंद्रित होती है तो उत्सर्जन अधिक हो जाता है।जब आय का यह संकेंद्रण आर्थिक शक्ति के साथ मेल खाता है, तो यह जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई का विरोध करता है। जितनी अधिक असमानता फैलती है, उतना ही अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है। यह आगे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की अवधि के समाधान में बाधा डालता है और तर्कों को प्रभावित करता है जो इसके हित की सेवा करते हैं।

जलवायु परिवर्तन के लिए गरीब कितना अधिक संवेदनशील है

1. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल की 2018 की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी लाखों लोगों के जल में रहने का कारण बन सकती है।

2. 2018 विश्व खाद्य कार्यक्रम की रिपोर्ट खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, ''मौसम की आपदाओं के कारण 23 देशों में, मुख्य रूप से अफ्रीका में, सूखे से संबंधित झटकों के कारण 39 मिलियन से अधिक लोगों को आपातकालीन देखभाल की आवश्यकता थी।"

3. आंतरिक विस्थापन पर 2018 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, ''2017 में 143 देशों और क्षेत्रों में 30.6 मिलियन नए आंतरिक प्रवास-संबंधी संघर्ष और प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई।''

4. ढाका में तटीय बाढ़, प्यूर्टो रिको में तूफान मारिया, या पश्चिम अफ्रीका में चाड झील के मरुस्थलीकरण के कारण दुनिया भर में जलवायु शरणार्थी पाए जा सकते हैं।यह अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोपीय संघ में शरण मांगने वाले लोगों की संख्या में 2100 तक 28% की वृद्धि होगी।

5. इससे मौजूदा संघर्षों के तेज होने की

संभावना बढ़ जाती है और नए भी बनते हैं। केप टाउन एक बड़ा उदाहरण है जहां 2015 में संकट शुरू हुआ था, और यह शहर पानी से बाहर निकलने वाला दुनिया का पहला बड़ा शहर बनने के खतरे में जी रहा है।

6. दूसरी ओर, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य वर्षा के समय और पैटर्न में बदलाव का अनुभव करता है, जिसके कारण खाद्य उत्पादन कम हुआ है और कृषि योग्य भूमि पर अधिक प्रतिस्पर्धा, देश में बढ़ते जातीय तनाव और संघर्ष साफ देखा जा सकता है।

इस तरह के संघर्षों और घटनाओं का गरीबों पर गहरा प्रभाव पड़ता है और इससे गरीबी और पलायन में वृद्धि होती है, जो लोगों को दुनिया भर में एक दुष्चक्र में धकेल देती है।

भारत पर प्रभाव

भारत के बारे में बात करने का मतलब है कि जलवायु परिवर्तन का भारत पर पड़े नाटकीय प्रभाव को देखना।

- ताप की लहरें अधिक से अधिक प्रच. लित होती जा रही हैं,2022 तक कई शहरों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है।
- 1950 के बाद से, भारी वर्षा की घटनाओं की संख्या तीन गुना हो गई है, लेकिन वर्षा में गिरावट आई है: भारत में एक अरब लोग अब साल में कम से कम एक महीने पानी की गंभीर कमी से पीड़ित हैं।
- भारत की एक तिहाई आबादी तट के किनारे रह रही है, जबकि पिछले दो दशकों में उत्तर हिंद महासागर में औसतन 3.2 मिमी प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है, समुद्र का स्तर खतरे में है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण हुए नुकसान के मामले में भारत विश्व में पांचवें स्थान पर है।

जलवायु परिवर्तन कम आय वाले और हाशिए के समुदायों को असमान रूप से प्रभावित कर रहा है।जो लोग अपने दैनिक भोजन के लिए बाहरी श्रम पर निर्भर हैं या जो भीड़भाड़ वाले, खराब हवादार घरों में रहते हैं, वे विशेष रूप से लंबे तापमान से पीड़ित हैं।देश के कम से कम 50% खेत बारिश पर निर्भर हैं, और बारिश में बदलाव से उनकी आजीविका पर बड़ा असर पड़ेगा।एक अध्ययन के अनुसार, कृषि उत्पादन में गिरावट और अनाज की बढ़ती कीमतों से 2040 तक भारत की राष्ट्रीय गरीबी दर में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, जिससे 50 मिलियन गरीब लोगों की वृद्धि हो सकती है।जलवायु परिवर्तन के कारण बार-बार आने वाली बाढ़ और सूखा भारत के कई हिस्सों में भोजन की कमी और बढ़ती खाद्य कीमतों का कारण बन रहा है। इससे अकाल और कुपोषण होता है, जो सबसे ज्यादा गरीब लोगों को प्रभावित करता है।

समय की आवश्यकता

ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करने के लिए 2050 तक शून्य CO2 उत्सर्जन और 2010 के स्तर की तुलना में 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन में 50% की कमी की आवश्यकता होगी।

नीतियां जो नाटकीय रूप से हमारे ऊर्जा और परिवहन के उपयोग, भोजन और अन्य संसाध नों का उत्पादन और उपयोग, और आश्रय की तत्काल आवश्यकता है। समस्या यह है कि इन नीतियों को कैसे लागू किया जाए।

कार्बन उत्सर्जन को कम करने की जिम्मेदारी उच्च आय वाले देशों के साथ-साथ कुछ विकासशील और विकासशील देशों में अधिक विशेषाधिकार प्राप्त नागरिक समाज समूहों द्वारा वहन की जानी चाहिए।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग की आदतों में उल्लेखनीय कमी की आवश्यकता होगी। COP21 के लक्ष्यों को पूरा करने का सबसे सुरक्षित तरीका असमानता को दूर करना और सामाजिक जिम्मेदारी को मजबूत करना है - खासकर अगर हमें वैश्विक औसत तापमान को केवल 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करने के बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करना है।

अन्य उपायों पर विचार किया जा सकता है

- थर्मल मीथेन स्टोव के उत्पादन के लिए इनडोर और सार्वजनिक बायोगैस इकाइयों की स्थापना;
- पारंपरिक लकड़ी से जलने वाले स्टोव को बदलना;
- सोलर लाइट प्रदान करना;
- स्मार्ट फोन अनुप्रयोगों जैसे सूचना प्रौद्योगि. की (आईटी) प्लेटफार्मों के उपयोग के माध्यम से वैज्ञानिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना।
- कम कार्बन वाली खेती की तकनीक लागू करना।

निष्कर्ष

कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इस मुद्दे को हल करने के लिए कितने प्रयास कर सकते हैं, लचीलापन और जलवायु परिवर्तन को मजबूत करने की चुनौती के लिए वास्तव में इस ग्रह पर विभिन्न समुदायों के ज्ञान का अनूठा परिप्रेक्ष्य, कौशल और धन सहायक साबित हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण होगा कि प्राप्त. कर्ताओं के रूप में देखे जाने के बजाय, हम प्रतिरोधक्षमता विकसित करने में प्रतिभागियों के रूप में काम करें।

NOTES

खाद्य तेल संकटः- कारण, प्रभाव और समाधान

प्रसंग-

छह खाद्य तेलों- मूंगफली तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, सोया तेल, सूरजमुखी तेल और पाम तेल की कीमतें पिछले एक साल में अखिल भारतीय स्तर पर 9% से 56% के बीच बढ़ी हैं।

परिचय-

कुछ दिनों की स्थिरता के बाद खाद्य तेल की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ने से मलेशियाई पाम तेल अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।महामारी की शुरुआत के बाद से विश्व स्तर पर और भारत में खाद्य तेल की कीमतें तीव्रता से बढ़ रही हैं। कीमतों में वृद्धि तीव्र है कि भारत सरकार को कीमतों में वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय करने पड़े।

भारत में खाद्य तेल की खपत-

बढ़ती आय और खाने की आदतों में बदलाव से खाद्य तेलों की खपत पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रही है। सरसों के तेल की सबसे ज्यादा खपत ग्रामीण इलाकों में होती है, रिफाइंड तेल सूरजमुखी तेल और सोयाबीन तेल की हिस्सेदारी शहरी इलाकों में ज्यादा होती है। 1993-94 और 2004-05 के बीच, खाद्य तेलों की मासिक प्रति व्यक्ति खपत ग्रामीण क्षेत्रों में 0.37 किलोग्राम से बढ़कर 0.48 किलोग्राम और शहरी क्षेत्रों में 0.56 किलोग्राम से बढ़कर 0.66 किलोग्राम हो गई। 2011-12 तक, यह ग्रामीण क्षेत्रों में 0.67 किलोग्राम और शहरी क्षेत्रों में 0.85 किलोग्राम तक बढ़ गया था। घरेलू स्रोतों के साथ-साथ आयात के माध्यम से वनस्पति तेलों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में लगातार वृद्धि से संकेतमिलता है कि मांग में वृद्धि जारी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में वनस्पति तेलों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 19.10 किलोग्राम से 19.80 किलोग्राम प्रति वर्ष रही है।

खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण-

- घरेलू खाद्य तेल उत्पादन खपत में वृद्धि के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है और आयात पर निर्भरता के कारण देश को भारी लागत का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दशकों के दौरान खाद्य तेलों में आयात वृद्धि लगभग 174 प्रतिशत रही है।
- पिछले पांच वर्षों में, भारत में तिलहन का उत्पादन 44 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है, जो 2015-16 में लगभग 25.3 मिलियन टन से बढ़कर 2020-21 में लगभग 36.6 मिलियन टन हो गया है। बहरहाल, यह भारत की खाद्य तेल की आधे से भी कम मांग को पूरा करता है। वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत के आंकड़ों के आधार पर 19 किलोग्राम प्रति वर्ष, भारत में 2.5 करोड़ टन खाद्य तेल की वार्षिक मांग है, जिसमें से केवल 10.5 मि. लियन टन घरेलू उत्पादन से आपूर्ति की जाती है। शेष 60 प्रतिशत की आपूर्ति आयात से की जाती है। फिलहाल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तिलहन और खाद्य तेल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, इसलिए घरेलू कीमतों पर असर पड़ रहा है।
- भारत प्रति माह लगभग 175,000-200,000 टन सूरजमुखी तेल का आयात करता है और रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष ने सूरजमुखी तेल की आपूर्ति को बाधित कर दिया है। फरवरी 2022 में सिर्फ 152,000 टन भारत पहुंचा और अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो आपूर्ति और घट सकती है। भारत की 22-23 लाख टन की वार्षिक कच्चे सूरजमुखी तेल की आवश्यकता का लगभग 90% यूक्रेन से 70% और 20% रूस से और शेष 10% अर्जेंटीना से आता है। नवंबर 2021 से शुरू होने वाले चालू तेल वर्ष के लिए मात्रा के हिसाब से सबसे अधिक आयात पाम तेल का रहा है।
- प्रमुख तेल निर्यातक देशों में इस प्रतिकूल मौसम के अलावा कोविड-19 महामारी से उपजी श्रमिकों की कमी के कारण तेल उत्पादकों के निर्यात में गिरावट आई है। सोयाबीन तेल की कीमतें पिछले साल सबसे बड़े निर्यातक अर्जेंटीना में शुष्क मौसम और भारत और चीन के प्रमुख उपभोक्ताओं की उच्च मांग के कारण बढ़ीं। यूक्रेन और रूस में सूखे जैसे हालात के कारण सूरजमुखी तेल की कीमतों में तेजी आई।
- हाल ही में इंडोनेशिया के कच्चे पाम तेल और इसके परिष्कृत उत्पादों, जैसे कि खाना पकाने के तेल की घरेलू बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध ने भी खाद्य तेल संकट को बढ़ा दिया क्योंकि इंडोनेशिया पाम तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।
- भारत चीन सहित पाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार है तो इसका असर भारत के ऊपर और अधिक पड़ने की संभावना है।
- मलेशिया, जो पाम तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, महामारी के कारण श्रम की कमी से जूझ रहा है और हाल में इस संकट से उबरता नहीं दिख रहा।

खाद्य तेल संकट का प्रभाव -

- खाद्य तेल की कीमतें घरेलू स्तर पर सख्त हो गई है और कीमतों की बढ़ोत्तरी में

महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहीहैं। वनस्पति तेलों की बढ़ती लागत मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने के भारत के प्रयासों के लिए एक लगातार बढ़ता खतरा है। दुनिया में सबसे ज्यादा खपत होने वाले खाद्य तेल पाम तेल की कीमतों में इस साल रिकॉर्ड 15% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि प्रतिद्वंद्वी सोयाबीन तेल में 12% की बढ़ोतरी हुई है, जो वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचने में योगदान देता है।

- यह भारत में पहले से ही बढ़ रही खुदरा मुद्रास्फीति को बढ़ा रहा है। चूंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल-दर-वर्ष में उम्मीद से अधिक बढ़कर 7.79% हो गई, जो लगातार चौथे महीने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 6% के सहिष्णुता बैंड से ऊपर रही।
- एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 24 प्रतिशत भारतीय परिवारों को इसकी खुदरा दरों में तेज वृद्धि के कारण खाद्य तेलों की खपत कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जबकि 29 प्रतिशत ने अपने खाना पकाने के तेल को सस्ता विकल्प उपलब्ध कराने के लिए कम कर दिया है।
- एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 24 प्रतिशत भारतीय परिवारों को इसकी खुदरा दरों में तेज वृद्धि के कारण खाद्य तेलों की खपत कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जबकि 29 प्रतिशत ने अपने खाना पकाने के तेल को सस्ता विकल्प उपलब्ध कराने के लिए कम कर दिया है।
- इस साल, भारत खाना पकाने के तेल के आयात पर लगभग $20bn (£16bn) खर्च करेगा, जो दो साल पहले खर्च किए गए खर्च से दोगुना है।

सरकार द्वारा उठाया गए कदम-

- अभी तक, सरकार के पास उत्पादकों से अपने मार्जिन में कटौती करने का आग्रह करने का सीमित विकल्प है। केंद्र खाद्य तेलों के आयात पर आयात शुल्क कम करने जैसे कई उपाय कर रहा है। पिछले साल नवंबर में, उसने कच्चे पाल, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर मूल आयात शुल्क को 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया था। इसने कच्चे पाम तेल के लिए कृषि अवसंरचना उपकर को 7.5 प्रतिशत और कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल के लिए 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। साथ ही रिफाइंड पामोलिन, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क को 32.5 प्रतिशत से घटाकर 17.5 प्रतिशत कर दिया।
- भारत आयात पर अपनी निर्भरता को दूर करने के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। सरकार ने आत्मनिर्भरता में सुधार के लिए पिछले साल खाद्य तेलों-तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन नामक 1.5 अरब डॉलर की पहल शुरू की थी।
- भारत का लक्ष्य 2025-26 में अनुमानित 1.12 मिलियन टन से कच्चे पाम तेल का उत्पादन 2029-30 तक 2.8 मिलियन टन से अधिक करना है।
- तिलहन की अधिक बुवाई के कारण इस वर्ष शीतकालीन फसलों की भूमि रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 4 फरवरी तक तिलहन फसल क्षेत्र लगभग 10.3 मिलियन हेक्टेयर (25.5 मिलियन एकड़) अनुमानित था, जो एक साल पहले की तुलना में 23% अधिक है।

आगे बढ़ने की राह-

- भारत को किसी भी मूल्य वृद्धि से बचाने के लिए एक खाद्य तेल भंडार का निर्माण करना चाहिए। इससे सरकार को कमी के समय आपूर्ति जारी करने, कीमतों में नरमी और सट्टा व्यापार और जमाखोरी पर अंकुश लगाने की क्षमता मिलेगी।
- चूंकि भारत ने तिलहन उगाने के लिए भूमि परिवर्तन में प्रगति दिखाई है, इसलिए सोयाबीन, सूरजमुखी और रेपसीड फसलों को उगाने के लिए अधिक भूमि का उपयोग किया जाना चाहिए।
- कुल तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद के लिए देश को अंततः भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित रेपसीड की ओर रुख करना चाहिए । सरसों का तेल भारत की 22.5 मिलियन टन की वार्षिक खाना पकाने के तेल की जरूरत का 10% से अधिक है। चूंकि जीएमओ में उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता है, इसलिए इसे सावधानी के साथ अपनाया जाना चाहिए।

NOTES

वर्तमान परिदृश्य में राजद्रोह कानून की प्रासंगिकता

सन्दर्भ

हाल ही में महाराष्ट्र में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। यहाँ यह स्थिति प्रश्नगत हो जाती है कि क्या एक जनप्रतिनिधि पर राजद्रोह वर्तमान लोकतान्त्रिक परिदृश्य में प्रासंगिक है?

परिचय

हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की राजनैतिक गतिविधियों में हलचल देखने को मिली जब महाराष्ट्र की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा से संबद्ध एक मामले (मुख्यमंत्री के निवास स्थान के सामने हनुमान चालीसा करने) में उनपर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इस मामले में एक बार पुनः राजद्रोह की प्रासंगिकता पर सवाल उठे। ध्यातव्य है कि भारतीय दंड सहिंता की धारा 124A में देशद्रोह की सजा का प्रावधान है। धारा 124A संहिता के अध्याय टप का हिस्सा है जो राज्य के खिलाफ अपराधों से संबंधित है।

क्या है राजद्रोह से सम्बंधित प्रावधान -भारतीय दंड सहिंता की धारा 124A -

- इस धारा के अनुसार – जो भी, शब्दों द्वारा, या तो लिखित या लिखित, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा, भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध घृणा या अवमानना में लाने के लिए या प्रयास करता है, या उत्तेजित करता है या उसके प्रति अप्रभाव को उत्तेजित करने का प्रयास करता है, उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या कारावास केसाथ जो तीन साल तक बढ़ सकता है, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है।
- **स्पष्टीकरण 1.** – अभिव्यक्ति ''अप्रभाव'' में अरुचि और शत्रुता की सभी भावनाएं शामिल हैं।
- **स्पष्टीकरण 2.** – सरकार द्वारा कानून के माध्यम से उनके परिवर्तन को प्राप्त करने की दृष्टि से कानून के उपायों के प्रति अस्वीकृति व्यक्त करते हुए टिप्पणियां, बिना रोमांच या घृणा, अवमानना या अप्रभाव को उत्तेजित करने के प्रयास के साथ, इस धारा के तहत अपराध का गठन नहीं करती हैं।
- **स्पष्टीकरण 3.** – सरकार द्वारा रोमांचक या बिना घृणा, अवमानना या अप्रभाव को उत्तेजित करने के लिए प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई की अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियां, इस धारा के तहत अपराध का गठन न करें। राजद्रोह के कानून का ऐतिहासिक विकास
- सर्वप्रथम यह कानून 17 वी शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में राजशाही तथा सरकार के विरोध को रोकने के लिए लाया गया था।
- भारत में राजद्रोह के कानून का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव 1837 में धारा 113 के रूप में परिकल्पित गया था परन्तु इसे सहिंता में स्थान नहीं मिला।
- 1870 में वहावी आंदोलन के दौरान इसे मुस्लिम उपदेशको के विरुद्ध सहिंताबद्ध किया गया जो भारत में ब्रिटिश राज के विरुध धर्मयुद्ध आरम्भ करने का उपदेश देते थे। यह कानून जेम्स स्टेफेन के सुझाव पर लाया गया था।
- 1898 के IPC संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1870 संस्करण को काफी हद तक संशोधित किया गया था। वर्तमान खंड इस 1898 के खंड के समान है।
- हालाँकि भारत के औपनिवेशिक और औपनिवेशिक इतिहास के विभिन्न बिंदुओं पर 1937, 1948, 1950 और पार्ट बी स्टेट्स (कानून) अधिनियम, 1951 में साधारण परिवर्तन किये गए।
- महात्मा गाँधी, बाल गंगाधर तिलक, शंकरलाल बैंकर इत्यादि लोगों पर इस अधि नियम के अंतर्गत मुकदमे चलाये गए।

वर्तमान समय में राजद्रोह कानून की प्रासंगि. कता के पक्ष में तर्क

- वर्तमान समय में भारत में लोकतंत्र पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो सका है। आतंकवाद , नक्सलवाद तथा क्षेत्रवाद से सम्बद्ध कई मुद्दे देश की राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता को प्रभावित करते है। इन चुनौतियों से निपटने हेतु राजद्रोह का कानून आवश्यक है।
- देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक असमानता देश में अराजकता को जन्म देती है। तथा जब तक 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' जैसे राष्ट्र विरोधी नारे रहेंगे तब तक राजद्रोह जैसे कानूनों की स्थिति बलवती रहेगी।
- इस सम्बन्ध में एक तर्क यह भी दिया जा सकता है कि जिस प्रकार न्यायपालिका की अवमानना तथा संसदीय अवमानना के लिए दंड का प्रावधान है उसी प्रकार राजद्रोह कार्यपालिका की अवमानना के लिए दंड के प्रावधान को सुनिश्चित करता है।
- भारत में (देश के अंदर तथा बाहर से भी) कई ऐसे अराजक तत्व सक्रिय हैं जो निर्वाचित सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। इन अरा. जक तत्वों को रोकने तथा निर्वाचित सरकार की स्थिरता के लिए राजद्रोह जैसे कानूनो का अस्तित्व में रहना आवश्यक है।

राजद्रोह की प्रासंगिकता के विपक्ष में तर्क

- यह कानून उपनिवेशी ताकतों को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रवादी गतिविधयों को रोकने के लिए लाया गया था। परन्तु वर्तमान समय के लोकतान्त्रिक भारत में ऐसे कानून यथोचित नहीं हैं।
- इस कानून में स्पष्टता का अभाव है। धारा 124 ए के तहत 'असंतोष' जैसे उपयोग किए जाने वाले शब्द अस्पष्ट हैं और जांच अधि कारियों की सनक और कल्पनाओं की विभिन्न

व्याख्याओं के अधीन हो जाते हैं।

- यह वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है। कई बार सरकारे नीतियों की आलोचना करने पर भी राजद्रोह लगा देती हैं। यह स्थिति लोकतंत्र तथा भारत की संसदीय प्रणाली के अनुकूल नहीं।
- भारत की संविधान सभा ने यह स्वीकारा था कि लोगों के विरोध के वैध और संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार को दबाने के लिये राजद्रोह कानून को एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए भारत की संविधान सभा ने इस कानून को संविधान में स्थान नहीं दिया था।
- यह कानून सरकार की निरंकुशता तथा राजनैतिक प्रतिशोध का प्रतीक बन चुका है। वर्तमान समय में इस कानून के कई दुरूपयोग देखे गए हैं यथा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दो तेलुगू (भाषा) समाचार चौनलों पर राजद्रोह की जबरदस्ती कार्रवाई , कन्हैया कुमार वाद इत्यादि। अत: इसे निरसित करना ही उचित है।
- यह कानून ब्रिटेन में लाया गया था। परन्तु अब यह कानून ब्रिटेन जैसे कई देशों में इसे निरस्त कर दिया गया है, इसलिए भारत में भी इसे निरस्त करने की मांग उठती है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1962 में केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में धारा 124। की संवैधानिकता को बरकरार रखा लेकिन इसे अव्यवस्था पैदा करने का इरादा, कानून एवं व्यवस्था की गड़बड़ी तथा हिंसा के लिये उकसाने की गतिविधियों तक सीमित कर दिया। परन्तु शिक्षाविदों, वकीलों, सामाजिक-. राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं और छात्रों के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाकर उच्चतम न्यायलय में निर्णयों की भी अवहेलना की जाती है।
- भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में अन्य प्रावधान हैं जो ''सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने'' या ''हिंसा और अवैध तरीकों से सरकार को उखाड़ फेंकने'' को अपराध बनाते हैं। इसलिए, धारा 124A की आवश्यकता नहीं है।

राजद्रोह का कानून तथा न्यायपालिका तारा सिंह गोपी चंद बनाम राज्य (1951)

1951 में पंजाब हाईकोर्ट ने धारा 124A को असंवैधानिक करार दिया था। 1959 में इला. हाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह का एक फैसला पारित किया गया था, न्यायलय ने यह कहा कि यह मुक्त भाषण के तत्वार्थ को प्रभावित करता है।

केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, 1962

सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1962 में केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में धारा 124। की संवैधानिकता को बरकरार रखा लेकिन इसे अव्यवस्था पैदा करने का इरादा, कानून एवं व्यवस्था की गड़बड़ी तथा हिंसा के लिये उकसाने की गतिविधियों तक सीमित कर दिया।

बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1995:-

उच्चतम न्यायालय ने खालिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाने के आरोप में लोगों को राजद्रोह के आरोपों से मुक्त कर दिया था। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि केवल दो व्यक्तियों द्वारा नारे लगाने को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस गतिविधि को सरकार के विरुद्ध नफरत या असंतोष को उत्तेजित करने का प्रयास भी नहीं माना जाता है।

निष्कर्ष

यह सत्य है कि इस कानून का दुरूपयोग किया जाता है जो लोकतान्त्रिक मूल्यों के विरुद्ध है परन्तु देश की एकता तथा अखंडता के दृष्टिकोण से इस प्रकार के कानून प्रासंगिक हैं। हालाँकि सरकार का यह दायित्व है कि राजद्रोह जैसे कानून के प्रयोग में अपवादात्मक स्थिति का प्रयोग करे क्योंकि किसी व्यक्ति पर राजसरोह का आरोप लगने के उपरांत वह दोषी नहीं है अथवा उसे बाद में दोषमुक्त कर दिया गया) उसकी तथा उसके परिवार की सामाजिक - राजनैतिक स्थिति में कमी आती है तथा सरकार से विश्वास में भी कमी आती है। अत: राजद्रोह की परिभाषा को केवल भारत की क्षेत्रीय अखंडता के साथ-साथ देश की संप्रभुता से संबंधित मुद्दों को शामिल करने के संदर्भ में संकुचित किया जाना चाहिये। इस कानून के मनमाने प्रयोग के सन्दर्भ में जागरूकता बढ़ाने के लिये नागरिक समाज को पहल करनी चाहिये।

NOTES

फार्मास्युटिकल नवाचार तथा उदयमिता

सन्दर्भ

हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने फार्मास्युटिकल नवाचार तथा उदयमिता पर दिशा निर्देश जारी किये हैं। ये दिशा-निर्देश भारतीय फार्मा उद्योग को प्रेरित करने के लिये शैक्षणिक संस्थानों के लिये जारी किये गए हैं।

परिचय

भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। इसके साथ ही कोरोना काल के दौरान भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र की क्षमता सम्पूर्ण विश्व में दिखी है। इस स्थित में यह आवश्यक है कि स्थिति भारत अपने फार्मास्युटिकल क्षेत्र को विश्वस्तरीय बनाये जिसके लिए नवाचार की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने भारतीय फार्मा उद्योग को प्रेरित करने के लिये शैक्षणिक संस्थानों के लिए फार्मास्युटिकल नवाचार तथा उदयमिता पर दिशानिर्देश जारी किये हैं।

दिशा-निर्देश के मुख्य उद्देश्य

- इन नीति दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य एकेडे. मिक अनुसंधान को नवीन और व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित करना है।
- यह नीतिगत दिशा-निर्देश उद्यमशीलता गतिविधियों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर आत्मनिर्भर भारत मिशन में योगदान को बढ़ाना है।
- यह एकेडेमिक संस्थाओ के फैकल्टी तथा छात्रों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करता है।
- यह नीति संभावित आविष्कारकों और उद्यमियों के लिये प्री-इन्क्यूबेसन और सामान्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिये संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के सिद्धांत से प्रेरित है।
- इस सन्दर्भ में वार्षिक बजट के निर्धारित प्रतिशत (न्यूनतम 1 प्रतिशत) का आवंटन किया जाना चाहिये, जिससे नवाचार और स्टार्टअप से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देकर इनका समर्थन किया जा सके।
- प्रदान की गई सेवाओं और सुविधाओं के बदले में एक संस्थान स्टार्टअप/स्पिन-ऑफ कंपनी में इक्विटी का एक निश्चित प्रतिशत (2-9.5%) प्राप्त कर सकता है, जो कर्मचारी के योगदान एवं प्रदान की गई सहायता और संस्थान की बौद्धिक संपदा के उपयोग पर आधारित होता है।
- उद्यमशीलता की पहल का मूल्यांकन नियमित आधार पारिभाषित प्रभाव मूल्यांकन मापदंडों जैसे कि बौद्धिक सम्पदा लिस्टिंग, विकसित उत्पाद और उनका व्यावसायी. करण एवं उत्पन्न रोजगारों की संख्या तथा स्टार्टअप के द्वारा किया जायेगा।
- छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिये उपस्थि. ति में छूट प्रदान कर उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिये, भले ही , उनकी उपस्थिति उपस्थिति 75% से कम हो, ताकि वे उद्यमशीलता की गतिविधियों को भी समय दे सकें और संस्थानों से जुड़े पीएचडी के छात्रों के लिये भी नियमों में उदारता लायी जाएगी।

भारत का फार्मास्युटिकल क्षेत्र

- भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। भारतीय दवा क्षेत्र विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग का 50%, अमेरिका में 40% जेनेरिक मांग और यूके में सभी दवाओं का 25% आपूर्ति करता है। विश्व स्तर पर, भारत दवा उत्पादन के मामले में मात्रा के आधार पर तीसरे और मूल्य के आधार पर 14वें स्थान पर है।
- वैश्विक फार्मास्युटिकल क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। देश में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का एक बड़ा पूल भी है, जो उद्योग को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखते हैं।
- वर्तमान में, एड्स (एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएंसी सिंड्रोम) का मुकाबला करने के लिए विश्व स्तर पर उपयोग की जाने वाली 80% से अधिक एंटीरेट्रोवायरल दवाओं की आपूर्ति भारतीय दवा फर्मों द्वारा की जाती है।
- भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार, अगले दशक में घरेलू दवा बाजार के 3 गुना बढ़ने की सम्भावना व्यक्त की गई है। भारत का घरेलू दवा बाजार 2021 में 42 अरब अमेरिकी डॉलर का है तथा 2024 तक 65 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है तथा 2030 तक 120-130 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।
- वित्त वर्ष 2015 में भारत का चिकित्सा उपकरणों का बाजार 10.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। 2020 से 2025 तक इस क्षेत्र के 37% की सीएजीआर से बढ़कर 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
- अगस्त 2021 में केयर रेटिंग्स ने सम्भावना व्यक्त की कि भारत का फार्मास्युटिकल व्यवसाय अगले दो वर्षों में 11% की वार्षिक दर से बढ़कर 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य तक पहुंच जाएगा।
- भारतीय दवा निर्यात वित्त वर्ष 2021 में 24.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वित्त वर्ष 2022 में 22.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर (फरवरी 2022 तक) था।
- देश का दवा क्षेत्र कुल व्यापारिक निर्यात में 6.6% का योगदान देता है। मई 2021 तक, भारत ने 71 देशों को कुल 586.4 लाख COVID-19 टीकों की आपूर्ति की,

जिसमें अनुदान (81.3 लाख), वाणिज्यिक निर्यात(339.7 लाख) और COVAX प्लेटफॉर्म (165.5 लाख) के तहत निर्यात सम्मिलित है।

भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

- भारत में मानव संसाधन पर्याप्त स्थिति में हैं इसके उपरान्त भी भारत नवाचार तथा उद्यमशीलता के मामले में पीछे है। इसके मुख्य कारण यह है कि भारत में शिक्षण संस्थान तथा निजी क्षेत्र अनुसन्धान में अधिक रूचि प्रदर्शित नहीं करते।
- वर्तमान समय में भारत की दवाओं में सक्रिय दवा सामग्री (Active Pharmaceutical Ingredients- API) का व्यापक प्रयोग हो रहा है। भारत लगभग 80% एपीआई चीन से आयात करता है। अत: बाह्य देशो के उत्पादों पर दवा क्षेत्र की निर्भरता एक बड़ी समस्या है। यह भारत में भारत आपूर्ति में व्यवधान और अप्रत्याशित मूल्य उतार-चढ़ाव की समस्या ला सकता है।
- भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र में तेजी से नीतिगत परिवर्तन होते हैं। भारत में अप्रत्याशित और लगातार घरेलू मूल्य निर्धारण नीति में बदलाव के कारण चुनौती उत्पन्न हो रही है। इसके फलस्वरूप निवेश एवं नवाचारों के लिये एक अस्पष्ट वातावरण की स्थिति उत्पन्न कर दी है।
- भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र के समक्ष कई बार गुणवत्ता अनुपालन की समस्या आती है। कई बार दवाओं के ट्रायल प्रक्रिया में समस्याए आती हैं।
- भारत का फार्मास्युटिकल क्षेत्र वैश्विक स्तर पर कम योगदान देता है। भारतीय दवा बाजार अनुमानत: 40 अरब अमेरिकी डॉलर का है हालाँकि यह 1.27 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक दवा बाजार का एक छोटा सा हिस्सा है।

फार्मास्युटिकल क्षेत्र में की गई सरकारी पहलें

- मार्च 2022 में, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री (एसपीआई) सुदृढ़ीकरण योजना की घोषणा की गई। इसके लिए वित्त वर्ष 21-22 से वित्त वर्ष 25-26 की अवधि के लिए कुल वित्तीय परिव्यय रु.500 करोड़ प्रदान करने का प्रावधान किया गया।
- नवंबर 2021 में, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मलेन में 40 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं में नियामक पर्यावरण, नवाचार के लिए धन, उद्योग-अकादमिक सहयोग और नवाचार बुनियादी ढांचे सहित कई विषयों पर विचार-विमर्श होगा।
- जून 2021 में, वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने 197,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय की घोषणा की। इसका उपयोग पांच वर्षों में फार्मास्युटिकल के 13 प्रमुख क्षेत्रों यथा सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री, दवा बिचौलियों और प्रमुख प्रारंभिक सामग्री में पीएलआई योजना के लिए किया जाएगा। 31 अगस्त, 2021 तक, पीएलआई योजना को कुल 278 आवेदनों प्राप्त हुए। इससे 55

विनिर्माताओं को लाभ होने की संभावना है।

- इसके साथ ही फार्मास्युटिकल्स विभाग ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और उच्च-स्तर का अनुसंधान करने के लिये राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों के रूप में राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (NIPERs) की स्थापना की है।

ख यह विभाग जल्द ही श्भारत में फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास व नवाचार को प्रेरित करने की नीतिश भी लेकर आ रहा है।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में भारत का फार्मास्युटिकल क्षेत्र तेजी से वृद्धि कर रहा है। परन्तु इसे वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने के लिए अभी लम्बा सफर तय करना है। नवाचार तथा उद्यमिता के द्वारा भारत तेजी से अपने फार्मास्युटिकल क्षेत्र को बढ़ा सकता है। स्टार्टअप इंडिया, पीएलआई जैसे योजनाओ के कारण भारत में तेजी से विनिर्माण बढ़ रहा है जिसका प्रभाव फार्मास्युटिकल क्षेत्र पर भी दिखा है। फार्मास्युटिकल क्षेत्र में वृद्धि से न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्थिति को भी मजबूती मिलेगी जैसा की कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान दिखा। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की यह पहल निश्चित ही भारत में फार्मास्युटिकल क्षेत्र को बढ़ाने में सहयोगी होगी।

NOTES

भारत और दुनिया पर श्रीलंका के आर्थिक संकट का प्रभाव

प्रसंग

हाल ही में श्रीलंका के प्रधान मंत्री महिंदा राजपक्षे ने सरकार विरोधी विरोध के कारण इस्तीफा दे दिया, जिसमें कम से कम 78 लोग घायल हो गए और अधिकारियों को देशव्यापी कर्फ्यू लगाना पड़ा। श्रीलंका में बढ़ते आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है।

परिचय

1948 में स्वतंत्रता के बाद से श्रीलंका सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। विदेशी भंडार की गंभीर कमी ने ईंधन, रसोई गैस और अन्य आवश्यक चीजों के लिए लंबी कतारें लगा दी हैं, जबकि बिजली कटौती और खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी ने लोगों के संकट और बढ़ा दिए। आर्थिक संकट ने श्रीलंका में राजनीतिक संकट भी पैदा कर दिया है।

श्रीलंका की वर्तमान स्थिति

- श्रीलंका के पास लगभग दो बिलियन अमरीकी डालर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जबकि वर्ष 2022 में कुल ऋण चुकौती लक्ष्य सात बिलियन अमरीकी डालर है। इसमें से 1 अरब डॉलर मूल्य के बांड जुलाई 2022 तक परिपक्व हो रहे हैं।
- श्रीलंका में बाहरी कर्ज 2005 से तेजी से बढ़ रहा है। 2005 में 11.3 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2010 में 21.7 अरब अमेरिकी डॉलर, 2015 में 43.9 अरब अमेरिकी डॉलर और कोविड महामारी के दौरान 2020 में 56.3 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।
- अकेले इस साल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपये में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है।
- पिछले सप्ताह चावल की खुदरा कीमत एक साल पहले के स्तर से 60 प्रतिशत अधिक थी, जबकि प्याज की कीमत 79 प्रतिशत, आलू की 66 प्रतिशत और एक अंडे की कीमत 93 प्रतिशत अधिक थी। -ऑन-साल।
- कुल मिलाकर, मार्च 2022 में हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़कर 18.7 प्रतिशत हो गई, जो फरवरी 2022 में 15.1 प्रतिशत थी। खाद्य मुद्रास्फीति मार्च में 30.2 प्रतिशत थी और बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति सार्वजनिक विरोध का कारण बनती है।

श्रीलंका के आर्थिक संकट के कारण-

- 2019 में तत्कालीन नवगठित सरकार ने श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था के विकास को पुनर्जीवित करने और मूल्य वर्धित कर (वैट) को इस आधार पर कम करने का वादा किया था कि कम कर की दर अधिक उपभोक्ता व्यय को आकर्षित करेगी जो उन्हें किए गए घाटे का भुगतान करेगी। लेकिन महामारी ने बढ़ते उपभोग व्यय के चक्र को बिगाड़ दिया और वैट में कर कटौती की विफलता का कारण बना।
- इस कदम ने वैश्विक बाजार से त्वरित नकारात्मक प्रभाव दिए। रेटिंग एजेंसीज ने श्रीलंका की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, जिससे उसे अधिक धन उधार लेने से रोक दिया गया क्योंकि उसके विदेशी भंडार में गिरावट आई थी।
- अप्रैल 2021 में, गिरते विदेशी मुद्रा भंडार को पुनर्जीवित करने के लिए, श्रीलंका ने सभी रासायनिक और अकार्बनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जैविक खेती में पूरी तरह से बदलाव की घोषणा की। देश की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा रासायनिक उर्वरकों के आयात पर खर्च किया जाता है। इसके बजाय, इसने अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाला, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ। चावल उत्पादन में आत्मनिर्भर श्रीलंका को छह महीने के भीतर चावल का आयात शुरू करना पड़ा। चाय निर्यात की एक प्रमुख वस्तु थी जि. सका कुल निर्यात आय में 16.57 प्रतिशत का योगदान था, लेकिन वो भी समाप्त हो गया ।
- 2019 में ईस्टर संडे बम विस्फोट और को. विड महामारी के कारण पर्यटन में गिरावट आई जो सकल घरेलू उत्पाद का 12.9 प्रतिशत है।
- श्रीलंका श्रमिकों की कमी का भी सामना कर रहा है। 2018 में, पर्यटन कौशल समिति के उद्योग निकाय के प्रमुख मलिक फर्नांडो ने कहा कि देश को अगले तीन वर्षों के भीतर पर्यटन क्षेत्र के 100,000 और कर्मचारियों की आवश्यकता है।
- चीनी, फार्मास्यूटिकल्स, ईंधन, दालें और अनाज जैसे आवश्यक सामानों के आयात पर देश की भारी निर्भरता ने संकट को और बढ़ा दिया।

भारत पर प्रभाव -

- जब भी श्रीलंका में कोई राजनीतिक या सामाजिक संकट होता है, तो बड़ी संख्या में शरणार्थी श्रीलंका से भारत आते हैं। पहला कारण यह है कि लोग एक ही तमिल सम. ुदाय के हैं जो सदियों से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और दूसरा यह कि श्रीलंकाई गृहयुद्ध के बाद श्रीलंकाई सरकार में जातीय तमिल समुदाय का विश्वास कम हो गया है। भारत के लिए शरणार्थियों की इतनी बड़ी आमद को संभालना मुश्किल हो सकता है।
- ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में अपनी स्थिति को देखते हुए भारत वैश्विक व्यापार के लिए कोलंबो के बंदरगाह पर काफी निर्भर है। भारत के ट्रांसशिपमेंट कार्गो का 60 प्रतिशत बंदरगाह द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत से जुड़े कार्गो, बदले में, बंदरगाह की कुल ट्रांसशिपमेंट

मात्रा का 70 प्रतिशत हिस्सा है। कोलंबो के बंदरगाह पर संचालन में कोई भी व्यवधान भारत को लागत और भीड़ के मुद्दों में वृद्धि के प्रति संवेदनशील बनाता है।

- भारत श्रीलंका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। 2005 से 2019 तक भारत से एफडीआई लगभग 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत 2019 में श्रीलंका के लिए 139 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एफडीआई का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत था। श्रीलंका में कोई भी अस्थिरता भारतीय कंपनियों के हितों को प्रभावित कर सकती है।

वैश्विक प्रभाव-

- श्रीलंका में निवेश करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में चीन, यूएसए, भारत, जाप. ान आदि थे और श्रीलंका में आर्थिक संकट ने निवेशकों के हितों को प्रभावित किया, जिससे वैश्विक निवेशकों के बीच इसकी विश्वसनीयता खो गई।
- जब भी श्रीलंका में कोई राजनीतिक या सामाजिक संकट आया है, पड़ोसियों ने श्रील. ंका से शरणार्थियों की एक बड़ी आमद देखी।
- श्रीलंका ने अपने इतिहास में पहली बार अपने ऋणों में चूक की है क्योंकि यह एक आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है जिससे श्रीलंका के लिए नया धन प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा।

श्रीलंका को सहायता-

- भारत ने जनवरी 2022 से मुद्रा की अदला -बदली, आवश्यक वस्तुओं के लिए क्रेडिट लाइन और ऋण टालने के माध्यम से नकदी की कमी से जूझ रहे श्रीलंका को लगभग 3 बिलियन डॉलर का विस्तार दिया है।
- भारत ने श्रीलंका को ईंधन आयात करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया क्योंकि देश हाल के दिनों में अपने विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से गिरावट के बाद आयात के लिए भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिससे इसकी मुद्रा का अवमूल्यन हुआ और मुद्रास्फीति बढ़ गई।
- भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 400$ मिलियन मुद्रा स्वैप, इस वर्ष की शुरुआत में विस्तारित, आवश्यक आयात के लिए एक बिलियन क्रेडिट लाइन चालू है और इसके तहत अब तक लगभग 16,000 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति की गई है।
- भारत ने एशियाई समाशोधन संघ के तहत श्रीलंका को कुल $1 बिलियन के ऋण के पुनर्भुगतान को स्थगित करने में मदद की है।
- 500 मिलियन डॉलर की क्रेडिट सुविधा के माध्यम से श्रीलंका को और 400,000 मीट्रिक टन ईंधन वितरित किया गया है।
- विश्व बैंक औषधीय दवाओं और स्वास्थ्य आवश्यकताओं, सामाजिक सुरक्षा, कृषि और खाद्य सुरक्षा और गैस की जरूरतों को पूरा करने के लिए श्रीलंका के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए दो चरणों में वित्तीय सहायता में $600 मिलियन का विस्तार करेगा।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) अपने आर्थिक कार्यक्रम पर अधिकारियों के साथ मिलकर काम करके और संकट के समय पर समाधान के लिए अन्य सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करके मौजूदा आर्थिक संकट को दूर करने के श्रीलंका के प्रयासों का भी समर्थन करेगा।

आगे का रास्ता-

- श्रीलंका को इस गहरे आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए केंद्र में एक स्थिर सरकार बनाना प्राथमिकता है।
- एक महत्वाकांक्षी राजकोषीय समेकन जो श्रीलंका के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाले राजस्व उपायों पर आधारित है। इसका कर-से-जीडीपी अनुपात कम है, इसमें आयकर और वैट दरों को बढ़ाने और छूट को कम करने की गुंजाइश है, जो राजस्व प्रशासन सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- साथ ही जल्द ही देश को या तो कर्ज का पुनर्गठन करना होगा या राहत पैकेज के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में जाना होगा।
- भारत के ग्रीन रेवोलुशन की तरह श्रीलंका को भी खाद्यान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है।

NOTES

बुलडोजर न्याय

संदर्भ -

देश पिछले कुछ हफ्तों से विध्वंस अभियान का उन्माद देख रहा है, कई राज्य सरकारों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कथित कानून तोड़ने वालों के खिलाफ बुलडोज का इस्तेमाल किया है। हाल ही में खरगोन में रामनवमी हिंसा के कथित संदिग्धों से जुड़ी कई संपत्तियों को गिराने से इस तरह के कदम की वैधता पर सवाल खड़े होते हैं।

परिचय -

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में भू-माफियाओं के चंगुल से 67,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को मुक्त करने के लिए मशीनरी के व्यापक उपयोग के लिए उत्तर प्रदेश में 'बुलडोजर बाबा' का उपनाम अर्जित किया। बहुमुखी बुलडोजर को पिछले कुछ वर्षों में प्रभावी प्रशासनिक उपयोग में लाया गया है, जिससे अंडरवर्ल्ड, अपराध सिंडिकेट और माफिया को एक स्पष्ट संदेश गया है कि उनकी अवैध रूप से अर्जित अचल संपत्ति अब सुरक्षित नहीं है - ऐसी संपत्तियां वास्तविक खतरे में हैं जमीन पर गिराए जाने के संबंध में। बुलडोजर का उपयोग बहुत प्रभावी ढंग से किया जाता था, मुख्य रूप से पहले सार्व. जनिक उपद्रव और अवरोधों को दूर करने के लिए, लेकिन भू-माफिया और कठोर अपराधियों से संबंधित अपराध की लूट के खिलाफ एक प्रभावी उपकरण के रूप में भी। यह प्रयोग तुरंत ही हिट हो गया और इसने जनता का दिल और दिमाग जीत लिया।

विध्वंस अधिनियम-

विध्वंस कानून के दायरे और प्रावधानों के भीतर हो सकता है, अन्यथा नहीं। ज्यादातर मामलों में, इस तरह के अवैध निर्माण मूल्यवान सरकारी भूमि पर किए गए और बनाए गए अतिक्रमण हैं। अन्य लक्षित श्रेणी ऐसे मामलों की है जहां शिकायतकर्ता द्वारा अपील के सभी चौनल समाप्त हो गए हैं, और संबंधित अधिकारियों, मुख्य रूप से राजस्व और नगरपालिका प्राधि करण, विभिन्न विध्वंस कानूनों के प्रावधानों के तहत काम कर रहे हैं, साथ ही सीआरपीसी की धारा 133, को भी अधिकार दिया गया है। अवरोधों, सार्वजनिक उपद्रवों आदि को दूर करने के लिए।

विध्वंस के संबंध में नगरपालिका कानूनों की अपनी मानक संचालन प्रक्रियाएं हैं; बेशक, विशेष हित समूह यह मानना चाहते हैं कि किसी भी संपत्ति को ध्वस्त करने का निर्णय हमेशा एकतरफा और विकृत होता है, इस बात को थोड़ा सा महसूस करते हुए कि ऐसी सभी कार्रवाइयां न्यायिक जांच के दायरे में हैं और परिस्थितियों के संबंध में कानून की अदालतों में पूछताछ की जा सकती है। विध्वंस का, क्योंकि कुछ भी जो प्रक्रियात्मक रूप से सही नहीं है, विध्वंस टीम के सदस्यों के करियर को गंभीर रूप से खतरे में डाल सकता है।

विध्वंस ड्रिल बहुत विस्तृत है, जिसमें नोटिस, फोटोग्राफी और संचालन की वीडियोग्राफी की सेवा शामिल है।

बुलडोजर के प्रयोग में अचानक क्यों आई उछाल-

पहले के सेटअपों में या तो समझौता किया गया था, दूसरी तरफ देखा गया था, या जमीन हथियाने वालों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। किसी भी मामले में, यह एक ऐसा उपाय है जो जनता के साथ इतना नीचे चला गया है कि बुलडोजर की बिक्री आसमान छू गई है।

यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार अवैध कब्जे से 1,800 रुपये की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने में सक्षम थी, जो कि सिर्फ हिमशैल की नोक लगती है, क्योंकि एक भी जिले या विभाग को ढूंढना मुश्किल है जहां अवैध अतिक्रमण और निर्माण हुआ है। महामा. री अनुपात नहीं माना। प्रौद्योगिकी के इस युग में, डिजीटल मानचित्र और ड्रोन और सीसी. टीवी निगरानी की एक प्रणाली होना आसान है, जो भूमि जोत और अतिक्रमण के प्रयास के संबंध में वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करता है। इस प्रकार जहां भी

अतिक्रमणकारियों की उचित आशंका है वहां तत्काल और प्रभावी हस्तक्षेप की अपार संभावनाएं हैं। खोई हुई सरकारी भूमि और संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र का श्रेय प्रशासन के इस पहलू को बहुत उच्च प्राथमिकता प्राप्त है। यह भी सर्वविदित है कि अधिकांश व्यक्ति जिन्होंने कानून के शासन का उल्लंघन किया

है, वे भी अवैध निर्माण में लिप्त हैं, और यहीं पर वे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उन्हें अतिक्रमण विरोधी अभियानों के अधीन करने का अवसर देते हैं।

अवैध अतिक्रमण के कानून और अधिकार-

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कानून है, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में अवैध निर्माण से निपटने के लिए एक विस्तृत प्रक्रियात्मक तंत्र शामिल है।

अवैध कब्जेदार को अपने व्यवसाय का औ. चित्य सिद्ध करने के लिए एक नोटिस की अनिवार्य आवश्यकता है। किसी भी दंडात्मक कार्रवाई को कानूनी रूप से लेने से पहले नोटिस देने और प्रभावित व्यक्ति को सुनवा. ई का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता

एक अनिवार्य शर्त है। नोटिस की आवश्यकता प्रक्रिया के दायरे में नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय का एक मौलिक सिद्धांत और कानून के शासन का एक पहलू है। 1979 में, संविधान के 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया, लेकिन अनुच्छेद 300। को पेश किया, जिसने संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा। अनुच्छेद 300। में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ''कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा''। सुप्रीम कोर्ट के बाद के फैसलों ने दोहराया है कि राज्य द्वारा संपत्ति से वंचित करने के लिए न केवल एक वैधानिक मंजूरी होनी चाहिए, बल्कि श्तर्कसंगतताश और 'उचित प्रक्रिया' की कसौटी का भी पालन करना चाहिए। 1985 में, ओल्गा टेलिस और अन्य के ऐतिहासिक निर्णय में। अ. बॉम्बे नगर निगम और अन्य, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां तक कि एक अतिचारी को भी उन्हें निष्कासित करने के लिए बल प्रयोग करने से पहले जाने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। 1978 में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के अब प्रसिद्ध मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे की व्याख्या करते हुए कहा कि ''कानून की उचित प्रक्रिया'' द्वारा स्थापित प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। कानून, यह समझाते हुए कि ऐसी प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर नगर निगम, लुधियाना बनाम इंद्रजीत सिंह नामक मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि यदि नगरपालिका कानून के तहत नोटिस देने की आवश्यकता प्रदान की जाती है, तो इस आवश्यकता का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए।

विध्वंस कार्रवाई का औचित्य-

अधिकारियों ने विध्वंस को अतिक्रमण हटाने की संज्ञा दी है, सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा है कि ये अभियान उन लोगों को लक्षित कर रहे हैं जिन पर अपराध करने का संदेह है या आरोपी हैं।

कुछ राजनीतिक नेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ विध्वंस एक समुदाय को लक्षित कर रहे हैं यानि किसी विशेष समुदाय के लिए सामूहिक सजा।

सामूहिक दंड का विचार, किसी भी तरह से, कई अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों के तहत निषिद्ध है, जिसमें 1949 का जिनेवा कन्वेंशन भी शामिल है, जिसे 1950 में भारत द्वारा अनुमोदित किया गया था।

किसी आरोपी के खिलाफ राज्य की कार्रवाई के उपचारात्मक उपाय के रूप में विध्वंस भारतीय कानून में पूरी तरह से अस्वीकृत है। देश में ऐसा कोई दंडात्मक कानून नहीं है जो किसी भी अपराध के दंड के रूप में विध्वंस का प्रावधान करता हो।

एक आपराधिक कृत्य के दंडात्मक परिणाम के रूप में विध्वंस अभियान के लिए कोई भी औचित्य पूरी तरह से आपराधिक न्याय के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है।

निष्कर्ष-

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और दिल्ली में हाल ही में बिना नोटिस की आवश्यकता का पालन किए विध्वंस अभियान प्रभा. वित व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ सर्वोच्च द्वारा निर्धारित कानून के दांतों का उल्लंघन प्रतीत होता है। कोर्ट। लेकिन राज्य सरकारों के अनुसार उचित नोटिस देने के बाद कार्रवाई की गई है।

''संदिग्ध'' व्यक्तियों की आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को गिराने के लिए बुलडोजर का उपयोग करने की विवादास्पद प्रथा निष्पक्ष न्याय की भावना के विरुद्ध है और इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के निवासियों को अपूरणीय क्षति होती है। न्यायसंगत और पारदर्शी कार्रवाई से प्रशासन की विश्वसनीयता हमेशा बढ़ेगी और फील्ड अधिकारियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाने की संभावना कम होगी।

NOTES

मुफ्त की राजनीति

चर्चा में क्यों

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में एक पी. आई. एल. द्वारा उन राजनीति दल के चिन्हों और रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने की अपील की गयी है। जो चुनाव के दौरान जीत हासिल करने हेतु जनता को मुफ्त उपहार और अन्य मुफ्त सेवायें देने का वादा करते है।

भारतीय राजनीति में मुफ्त उपहार और सेवाएं -

भारतीय निर्वाचन में बहुदलीय प्रणाली की व्यवस्था है। प्रत्येक छोटे बड़े दल सत्ता में आने या सहयोग हेतु चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते है और चुनावी अभियानों द्वारा अपने मत का प्रचार करते हैं।

- हाल ही में सम्पन्न भारतीय राज्य विधान सभाओं चुनावो मे विभिन्न दलों द्वारा लोगों को उनके पक्ष में मत देने हेतु मुफ्त के उपहार एवं सेवाए देने की घोषणा की गई।
- वर्षो से मुफ्त की राजनीति चुनाव का एक अभिन्न अंग रहा है। हाल के चुनाव भी इससे अछूते नही रहे कुछ राजनीतिक दल मुफ्त बिजली, कुछ बेरोजगारों, दिहाड़ी मजदूरों और महिलाओ को मासिक भत्ता आदि देने का वादा करते दिखाई दिये। स्कूटर, स्मार्टफोन, लैपटाप आदि भी इसी का हिस्सा है।
- मुफ्त की राजनीति ने चुनाव के बाद की अवधि के लिए शासन को गंभीर मुद्दो को उठाया है यहां तक कि भविष्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की व्यवहार्यता के बारे में बुनियादी सवाल भी उठाए हैं।
- वही दूसरा तरफ सरकार द्वारा दी जाने वाली कुछ मुफ्त की योजनाओं द्वारा लक्षित समूह/वर्गों को जीवन जीने में राहत भी देती है। जैसे मुफ्त भोजन, विशेष रूप कोविड के दौरान गरीबी रेखा के नीचे के वर्गो को और कोविड टीकाकरण आदि।
- हालांकि मुफ्त की राजनीति आजादी के बाद से चली आ रही परन्तु इसकी अधिकता और अविवेकपूर्ण किये गये वादे संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव बना सकते है और चौतरफा विकास को बाधित कर सकते हैं।

पक्ष

कल्याणकारी राज्यः

- एक जागरूक समाज की लोकतान्त्रिक सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करे जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है परन्तु इन बुनियादी सेवाओं में भारी कमी है।
- कल्याणकारी सरकार से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उसके निर्णयों द्वारा जन सामान्य का जीवन स्तर ऊपर होगा।

समाज में असमानता

- भारतीय समाज में अमीर और गरीबों में वृहद् असमानता है। सरकारें इस असमानता को दूर करने के लिए प्रतिबंध है और उनका प्रयास लोगो तक संसाधन की पहुंच बना कर असमानता दूर करने का होता है।

किसान गरीब और उपेक्षित वर्गों के लिए मददगार -

- सरकारों द्वारा दी जाने वाली कुछ बहुत ही उपयोगी मुफ्त सुविधाएं और सब्सिडी है जो गरीबों की बुनियादी समस्याओं से निपटने और गरिमा पूर्ण जीवन जीने हेतु कारगर है। जैसे- खाद्य और पानी सब्सिडी जो एक स्वस्थ और सशक्त भारत बनाने में कड़ी का कार्य करती है।
- कृषि को टिकाऊ और लाभप्रद बनाने हेतु कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी।

आपातस्थिति के दौरान मददगार

- कोविड दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आपदा है। इसी दौरान सरकार द्वारा दी जाने वाली मुफ्त भोजन, स्वस्थ जानकारी, बेड पैमाने के मुफ्त टीकाकरण ने इस महामारी का विवेक पूर्ण प्रबंधन किया।
- इसी प्रकार अन्य प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों से सरकार द्वारा दी जाने वाली मुफ्त सेवा और सुविधा लोगो को राहत देती है।

आर्थिक धक्का

- गरीबो और लक्षित वर्गों को दी जाने वाली मुफ्त पेंशन अन्य वित्तीय मुद्दों से अर्थव्यवस्था में खपत/मांग का प्रोत्साहन मिलता है जो विकास दर को और कम होने से रोकता है।
- मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ, मानव विकास में सुधार लाते हैं जिससे श्रम की उत्पादकता में वृद्धि है।

सामाजिक स्थिरता

- भारतीय समाज में असमानता से लोगों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है परन्तु सरकार अपनी इन मुफ्त सेवा और सुविधाओं द्वारा इस असंतोष को दूर करने में सक्षम है।

विपक्ष

लोकतंत्र की भावना को कमजोर करता है

- लोकतांत्रिक पद्धति से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने अतिआवश्यक है। परन्तु प्राथमिक चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों ने मुफ्त की वस्तुओं द्वारा, वोट के बदले नोट का विकल्प तैयार किया है। लोग उनके द्वारा दिये

जाने वाले मुफ्त प्रोत्साहन के आधार पर वोट देते है। उनके प्रदर्शन के आधार पर आंकने में विफल रहते हैं और योग्यता के आधार पर मत नहीं देते है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि मुफ्त खोरी स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनावों को जड़ से हिला देती है।

उत्पादकता मे गिरावट

- मुफ्त की वस्तुयें/उपहार लोगो में यह भावना पैदा करते हैं कि जीवन कम प्रयासों से भी किया जा सकता है। इससे श्रम के प्रति उदासीन हो जाते हैं जिससे उत्पादकता का ह्रास होता है। उदाहरण स्वरूप लोग बैंक से ऋण लेते हैं और चुनाव के दौरान छूट की उम्मीद से उसे नहीं चुकाते यह उत्पादकता तथा नैतिक खतरे को जन्म देती है।

राजकोष पर आर्थिक बोझ

- सत्ता के लिए इस तरह के आश्वासन से सत्ता में आने के बावजूद, एक वास्तविक संकट संसाधनों का होगा।
- विजित सरकारे कुछ विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कम से कम कुछ वादों को पूरा करने हेतु प्रयासरत होंगी। पहले से खराब वित्तीय संपत्ति वाले राज्यों में भारी वित्तिय संकट उत्पन्न होगा और राजकोष पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।
- अगर संसाधनों का प्रयोग इन मुफ्त की चीजों को देने में होगा तो राज्य में अपने ऋणों को देने का विफल होगी।

कर दाताओं पर नकारात्मक प्रभाव

- मुफ्त की राजनीति एक ईमानदार करदाता के मन में असंतोष की भावना उत्पन्न कर सकता है क्योंकि उनके द्वारा दिये गये कर का उपयोग मुफ्त के वादों को पूरा करने किया जा रहा है न कि सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए।

कार्य संस्कृति में कमी

- राजनीतिक दलों द्वारा दिये जाने वाले इन वादों से लोगों की इच्छायें बढ़ेगी और यही इच्छा आगे जाकर मांग के परिवर्तित हो सकती जिससे लोगो को काम करने की प्रवृत्ति में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नैतिकता घटेगी और परिणामस्वरूप राजनेताओं के हाथों की कठपुतली बन जायेंगे।

संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा

- मुफ्त पानी और बिजली संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा देंगे। उदाहरणस्वरूप पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य जहाँ भूजल का अधिक दोहन किया जाता है।

आगे की- राह

चुनाव आयोग -

- चुनाव आयोग को अधिक से अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। जैसे किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति, अवमानना की शक्ति आदि।

सार्वजनिक लाभ-

- सार्वजानिक व्यय दक्षता में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है जो परिणाम पर आधारित हो न कि केवल व्यय पर।

जागरुकता-

- लोगो को समझना होगा कि उन्हें मुफ्त की वस्तुएं या स्वतंत्रता दोनों में से क्या चुनना है? ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते।
- यह भी समझना होगा कि चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से निजी वस्तुओं का वितरण, जो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नहीं है वह समानता के विरुद्ध है।

राजनीतिक दल

- राजनीतिक दलों को चुनावी अभियानों में ऐसे वादे नही करने चाहिए जिसका समर्थन उचित नीतियो, बजटीय आवंटन और उन्हें वितरित करने के लिए एक प्रशासनिक ढांचे द्वारा न हो।

सरकार

- सरकार को धन का व्यय रोजगार सृजन में करना चाहिए न कि मुफ्त की चीजों को बाटने में।

निष्कर्ष

- मुफ्त की राजनीति आजादी के बाद से चली आ रही है। राजनीति दल प्रतिस्पर्था पर बढ़त लेने और मतदाताओं के दिमाग पर भावनात्मक नियंत्रण हासिल करने का एक सुविधाजनक तरीका मानते हैं। परन्तु अविवेकपूर्ण मुफ्त की राजनीति, अंततः राज्य को दिवालिया कर सकती है।
- चुनाव आयोग ने भी यह बात कही है कि मुफ्त के समान अवसर को बाधित करते हैं और स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया खराब करते हैं।
- नीति आधारित एक विस्तृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को लाने में कुछ भी गलत नहीं है वह समाज को विकास के रास्ते में आगे बढ़ाती है।
- इसी प्रकार सरकारों की कुछ योजना व अभियान केवल राजनीतिक उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए होते है जबकि कुछ योजनाओं की सराहना अन्तराष्ट्रिय मंचो द्वारा की जाती है। उदाहरण स्वरूप चुनाव पूर्व प० बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अभियान "दुआरे सरकार" और वही दुसरी तरफ लक्षित वर्गों को राहत देती हुई कन्या श्री कार्यक्रम आदि।

NOTES

राष्ट्रीय

1 लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) मुद्दा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के चेयरमैन आकार पटेल समेत कई अहम शख्सियतों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया है।

लुकआउट सर्कुलर क्या है?

यह पुलिस, जांच एजेंसी या यहां तक कि बैंक द्वारा वांछित किसी भी व्यक्ति को किसी देश या जगह को हवाई और बंदरगाह के माध्यम से छोड़ने या प्रवेश करने से रोकने के लिए एक नोटिस है। इमिग्रेशन को ऐसे किसी भी व्यक्ति को रोकने का काम सौंपा जाता है जिसके खिलाफ इस तरह का नोटिस देश छोड़ने या देश में प्रवेश करने से रोकता है। देश भर में 86 इमिग्रेशन चेक पोस्ट हैं। मानदंडों के अनुसार, एक एलओसी अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए वैध रहेगा और यदि एजेंसी से कोई नया अनुरोध नहीं किया जाता है तो इसे स्वचालित रूप से पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा।

एलओसी कौन जारी कर सकता है?

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), आयकर, राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों सहित बड़ी संख्या में एजेंसियां एलओसी बनाने के लिए अधिकृत हैं। अधिकारी एक जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक या केंद्र सरकार में एक उप सचिव के पद से नीचे नहीं होना चाहिए।

एलओसी जेनरेट करने के लिए आवश्यक विवरण क्या हैं और इसे कौन जारी करता है?

मंत्रालय के 2010 के एक आधिकारिक ज्ञापन के अनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) संख्या, और कोर्ट केस नंबर जैसे विवरण नाम, पासपोर्ट नंबर और अन्य विवरण के साथ अनिवार्य रूप से प्रदान किए जाने हैं। एमएचए के तहत बीओआई (आव्रजन ब्यूरो) केवल निष्पादन एजेंसी है। वे विभिन्न एजेंसियों के अनुरोधों के आधार पर एलओसी उत्पन्न करते हैं।

बैंक कैसे अधिकृत होते हैं?

शराब कारोबारी विजय माल्या, व्यवसायी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी सहित कई व्यवसायियों के ऋण में चूक और देश से भाग जाने के बाद, 2018 में एमएचए ने 2010 के दिशानिर्देशों में बदलाव किया, जिसमें सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को उन व्यक्तियों के खिलाफ जो देश के आर्थिक हितों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, एलओसी जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

क्या व्यक्ति किसी भी उपचारात्मक उपाय के हकदार हैं?

एलओसी को रद्द कराने के लिए कई नागरिकों ने अदालतों का रुख किया है। गृह मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि हिरासत के समय ''एलओसी का विषय नहीं दिखाया जा सकता है'' और न ही कोई पूर्व सूचना प्रदान की जा सकती है क्योंकि यह एलओसी के उद्देश्य को विफल करता है।

आगे की राह-

एलओसी केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित असाधारण मामलों के लिए जारी किया जाना चाहिए। यात्रा के अधिकार पर कोई निरंकुश नियंत्रण या प्रतिबंध नहीं हो सकता क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय (एमएचए) और आव्रजन ब्यूरो (बीओआई) को प्रभावित व्यक्ति को जारी एलओसी की एक प्रति प्रदान करने, एलओसी जारी करने के कारणों को बताने और निर्णय के बाद अपनी बात रखने का अवसर देना चाहिए।

2 'भारत टैप' पहल

जीवन में पानी के महत्व से हम भली-भांति परिचित हैं, पानी के बिना जीवन की कल्पना करना नामुमकिन सा है। इसलिए इसके संरक्षण के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की तरफ से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आवास और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा 'प्लम्बेक्स इंडिया' प्रदर्शनी में एक 'भारत टैप' पहल की शुरुआत की गई।

देश में स्वच्छता और जल संरक्षण के प्रति लोगों को सजग बनाने के लिए 'प्लम्बेक्स इंडिया' प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यह प्रदर्शनी नल से संबंधी उपकरणों, पानी और स्वच्छता उद्योग से संबंधित उत्पादों और सेवाओं के प्रदर्शन के लिए आयोजित की गई है। इसी प्रदर्शनी में आवास और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक 'भारत टैप' पहल

की शुरुआत की है। बाथरूम में लगी टोटी का मुंह अगर थोड़ा छोटा कर दिया जाए तो उससे पानी कम निकलेगा और इस तरह पानी का खपत कम होगा। 'भारत टैप' पहल का भी यही उद्देश्य है। इसके तहत कम प्रवाह वाले सेनेटरी-वेयर बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराए जाएंगे और इस तरह स्रोत पर पानी की खपत में कमी आएगी।

इसी कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री पुरी ने नारेडको माही की 'निर्मल जल प्रयास' पहल की भी शुरूआत की। इस पहल के तहत हर साल 500 करोड़ लीटर पानी बचाने के लिए काम किया जाएगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के संरक्षण में स्थापित राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (NAREDCO), राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष निकाय है। यह रियल स्टेट विकास के विभिन्न पहलुओं में शामिल हितधारकों का प्रतिनिधित्व करता है। सन 2021 में इसी NAREDCO की एक महिला शाखा की स्थापना की गई, जिसे नारेडको माही कहा जाता है। यह महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और रियल एस्टेट क्षेत्र व संबद्ध क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। यह एक ऐसे वातावरण के निर्माण का प्रयास करता है जहाँ रियल एस्टेट क्षेत्र में महिलाएँ अपना अनुभव साझा करने, अपने कौशल का उपयोग करने, संसाधनों को जुटाने, प्रभावित करने और स्थायी परिवर्तन लाने के लिये एक साथ आ सकें।

दरअसल जल की मांग में वृद्धि, इसका सीमित स्टोरेज, भूजल का मनमाना दोहन, तमाम वजहों से जल का लगातार प्रदूषित होना, इसका ठीक से विनियमन ना किया जाना और वनों की अंधाधुंध कटाई यह तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जल संरक्षण की नितांत जरूरत है। सरकार की तरफ से इसके लिए कई कदम भी उठाए गए हैं जिनमें स्वच्छ भारत मिशन, AMRUT मिशन, राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (NAQUIM), मनरेगा, जल क्रांति अभियान और राष्ट्रीय जल मिशन आदि शामिल है। इसके अलावा नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जल शक्ति मंत्रालय का गठन, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान और राष्ट्रीय जल पुरस्कार जैसे पहल भी सरकार द्वारा किए गए हैं।

NOTES

अंतर्राष्ट्रीय

1 ताइवान के प्रति अमेरिकी नीति में बदलाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करेगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका की वन चाइना पॉलिसी

'वन चाइना' एक लंबे समय से चली आ रही अमेरिकी नीति है जो बीजिंग के साथ उसके संबंधों का आधार है। नीति के तहत, अमेरिका ने ताइवान में चीन गणराज्य (आरओसी) के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध तोड़ दिए और 1979 में बीजिंग में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) के साथ संबंध स्थापित किए। दिसंबर 1978 के यूएस-पीआरसी संयुक्त विज्ञप्ति में नीति की रूपरेखा की व्याख्या की गई थी, जिसमें कहा गया था कि चीन का जनवादी गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका एक दूसरे को पहचानने और 1 जनवरी, 1979 तक राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के जनवादी गणराज्य की सरकार को चीन की एकमात्र कानूनी सरकार के रूप में मान्यता देता है। इस संदर्भ में, संयुक्त राज्य के लोग ताइवान के लोगों के साथ सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और अन्य अनौपचारिक संबंध बनाए रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार चीन स्थिति को स्वीकार करती है कि एक चीन है और ताइवान चीन का हिस्सा है।

अमेरिका ने अपने ताइवान संबंधों को कैसे बनाए रखा?

इसकी शुरुआत 1971 की ''पिंग-पोंग डिप्लोमेसी'' से हुई। उसी साल अप्रैल में, अमेरिका और ताइवान दोनों पक्षों के मध्य टेबल टेनिस मैच की शुरुआत से हुई थी। इससे इनके संबंधों में मधुरता आई। 1979 में, जब पीआरसी और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक-दूसरे की

राजधानियों में राजदूतों को तैनात किया, तब अमेरिकी कांग्रेस ने ताइवान संबंध अधिनियम (टीआरए) पारित किया। अधिनियम ने यह स्पष्ट कर दिया कि चीन के जनवादी गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का संयुक्त राज्य का निर्णय इस उम्मीद पर टिका है कि ताइवान का भविष्य शांतिपूर्ण तरीकों से निर्धारित किया जाएगा।

यह ताइवान को ''एक रक्षात्मक चरित्र के साथ'' और ''संयुक्त राज्य की क्षमता को बनाए रखने के लिए बल या अन्य प्रकार के जबरदस्ती का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ताइवान के लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा"।

''टू चाइनास'' स्थिति का इतिहास-

दो दशकों से अधिक समय के बाद 1949 में कम्युनिस्ट ताकतों द्वारा चीनी गृहयुद्ध जीतने के बाद, चीन गणराज्य ने अपनी राजधानी ताइपेई, ताइवान में स्थानांतरित कर दी। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना बीजिंग के साथ इसकी राजधानी के रूप में हुई थी। दोनों सरकारों ने पूरे चीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिस्पर्धी दावे किए, लेकिन उस समय केवल कुछ ने ही पीआरसी को मान्यता दी। यह बाद में 1971 में पीआरसी संकल्प 2758 के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश करने में कामयाब रहा, जिसने आरओसी को ''चीन'' के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में हटा दिया। अमेरिका ने 1979 तक पीआरसी को मान्यता नहीं दी थी।

निष्कर्ष

वन चाइना पॉलिसी एक संतुलनकारी कार्य है जिसमें अमेरिका चीन के साथ आधिका. रिक संबंध बनाए रखता है, और ताइवान के साथ एक अनौपचारिक संबंध रखता है। चीनी आक्रमण के मामले में ताइवान को सैन्य मदद के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का हा. लिया बयान चीन और ताइवान के बीच संतुलन को बिगाड़ सकता है।

2 फिनलैंड और स्वीडन का नाटो में शामिल होगे

संदर्भः-

फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो का हिस्सा बनने की इच्छा व्यक्त की है। ये घोषाएं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक झटका हैं, जिनकीविदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण फोकसनाटो को कमजोर करने पर रहा है।

नाटो में शामिल होने से लाभ-

सैन्य लाभ

सामूहिक सुरक्षा

इस संधि के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि यदि एक सहयोगी पर हमला होता है, तो इसे सभी पर हमला माना जाएगा।

यह रणनीतिक रूप से विकसित देशों की दीर्घकालिक सामूहिक रक्षा प्रदान करता है। जब 9/11 के आतंकवादी हमले हुए, तो अन्य सभी सदस्यों ने अफगानिस्तान में आतंकवाद-विरोधी जवाबी कार्रवाई में योगदान दिया।

साइबर रक्षा क्षमताएं

निवेश और चल रहे प्रशिक्षण के माध्यम से अपने बचाव को बढ़ाने में मदद करता है।

साइबर रक्षा विशेषज्ञ उन संगठनों के साथ काम करते हैं जो किसी भी देश को हमले से बचाने के लिए नेटवर्क में एक साथ आ जाते हैं।

आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का विकास करना

आतंकवाद की जांच के लिए नेपल्स, इटली में सहयोगियों के लिए एक केंद्र स्थापित किया गया है।

लागत प्रभावी रक्षा

प्रत्येक देश को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2% रक्षा पर खर्च करना चाहिए (वेल्स शिखर सम्मेलन, 2014) प्रत्येक सदस्य के हितों की रक्षा की जाती है और एक प्रभावी सेना को बनाए रखने की लागत देशों के बीच वितरित की जाती है।

आर्थिक लाभ

सदस्यों के बीच मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से सदस्य राष्ट्र के सामान को दुनिया के बाकी हिस्सों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है।

राजनीतिक लाभ

यह राष्ट्रों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता है। यह अपने घटक सदस्यों की संप्रभुता को कम नहीं करता है। चूंकि निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, प्रत्येक राष्ट्र की के विचारों का सम्मान किया जाता है।

नाटो सदस्यों और रूस की प्रतिक्रिया तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड की नाटो में शामिल होने का विरोध किया है।

- यू.एस. और यू.के. नाटो के विस्तार के पक्ष में हैं।
- जर्मनी और फ्रांस अधिक सतर्क रुख अपना रहे हैं।
- हंगरी, जिसके रूस के साथ गहरे संबंध हैं और रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने की यूरोपीय संघ की योजना पर सहमत हैं, ने नाटो के विस्तार पर अपने विचार स्पष्ट नहीं किए हैं।
- रूस, नाटो के किसी और विस्तार के जवाब में सैन्य जवाबी कार्रवाई की धमकी देता रहा है।

आगे की राह

- नाटो के सदस्यों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या नाटो के विस्तार से यूरोप में और शांति और स्थिरता आएगी।
- यह विस्तार, परमाणु हथियारों से लैस रूस और नाटो के बीच मौजूदा संकट को खतरनाक स्तर तक बढ़ा देगा।
- नाटो विस्तार के कई दौर और रूस की क्षेत्रीय आक्रामकता ने 1962 के क्यूबा

मिसाइल संकट के बाद से दुनिया को सबसे खतरनाक क्षण में ला दिया है।

- रूस को युद्ध रोकना चाहिए और सभी हितधारकों को इस मानव निर्मित संकट को समाप्त करने के लिए बातचीत और कूटनीति को फिर से शुरू करना चाहिए।

निष्कर्ष

रूस का ध्यान युद्ध समाप्त करने पर होना चाहिए न कि नाटो के विस्तार पर। तभी हम मानवता की बेहतरी के लिए कोविड के बाद की वैश्विक व्यवस्था का पुनर्निर्माण शुरू कर सकते हैं और महामारी से हुए नुकसान की कुछ भरपाई कर सकते हैं।

पर्यावरण

1 ईंधन सम्मिश्रण

चर्चा में क्यों है-

केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य को पांच साल तक अर्थात 2030 तक बढ़ा दिया है।

इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम

पृष्ठभूमि- केंद्र सरकार ने 2001 में एस 5% मिश्रित पेट्रोल के लिए पायलट परियोजना शुरू की थी, जिसके अंतर्गत 2003 तक 5% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया । वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए एक रोडमैप लॉन्च किया गया है।

जैव ईंधन - कोई भी ईंधन जो बायोमास से प्राप्त होता है उसे जैव ईंधन के रूप में जाना जाता है।

पूर्ण सम्मिश्रण से हमारा क्या तात्पर्य है?

ईंधन सम्मिश्रण ईंधन में अतिरिक्त पदार्थों के मिश्रण की एक प्रक्रिया है और इस विशिष्ट मामले में यह इथेनॉल है जिसे मिश्रित किया

यह क्या परिकल्पित करता है?

इथेनॉल बायोमास से उत्पादित एक कार्बनिक यौगिक एथिल अल्कोहल है। इसमें गैसोलीन की तुलना में अधिक ऑक्टेन संख्या होती है, जिससे ईंधन की ज्वलनशीलता बढ़ जाती है और इसलिए उत्सर्जन कम हो जाता है।

बायो ईंधन नीति क्या है?

जैव ईंधन नीति को 2018 में लाया गया था जिसका उद्देश्य ईंधन में इथेनॉल के मिश्रण को प्रोत्साहित करके, कच्चे तेल पर आयात निर्भरता को कम करना था । साथ ही बायो सीएनजी, बायोडीजल पर भी ध्यान देना था।

मुख्य विशेषताएं

1. इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम।
2. दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल उत्पादन।
3. ईंधन समिश्रण के लिए उत्पादन के लिए क्षमता बढ़ाना
4. फीडस्टॉक में अनुसंधान एवं विकास

इथेनॉल का निर्माण -

इथेनॉल मुख्य रूप से गेहूं और अन्य अनाज के अवशेषों के साथ-साथ चीनी कारखानों से प्राप्त किया जाता है।

इथेनाल के उपयोग -

यह सम्मिश्रण निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है

1. उन्नत दहन कार्बन मोनोऑक्साइड इस प्रदूषण को कम करने वाले गुणवत्ता प्रबंधन हैं
2. ईंधन आयात में लगभग $4 बिलियन की कमी
3. किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करता है यदि वे ऐसे उत्पाद उगाते हैं जो इथेनॉल उत्पादन में सहायक होता है।
4. बीमार चीनी उद्योगों का समर्थन करने में वाहनों को रबरयुक्त पुर्जों, प्लास्टिक घटकों के इलास्टोमर्स, जो ई-20 के साथ संगत हैं। ई-20 ईंधन के उपयोग के लिए इष्टतम रूप से डिजाइन किए गए इंजनों के साथ उत्पादित किए जाने की आवश्यकता होगी।

वर्तमान में सम्मिश्रण स्थिति :-

भारत में वर्तमान में एथेनाल सम्मिश्रण 9.90% है।

मुद्दे क्या हैं?

चीनी उद्योग उत्साहित नजर आ रहे हैं लेकिन रिपोर्ट्स फंड संकट की ओर इशारा कर रही है। चीनी उद्योगों की कमजोर बैलेंस शीट को देखते हुए, बैंकों द्वारा चीनी मिलों को वित्त देने में अनिच्छुक होने का दावा किया जाता है। मौजूदा प्रावधानों में खरीद के 21 दिनों के भीतर भुगतान की मंजूरी की परिकल्पना की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस सम्मिश्रण प्रतिशत का सुझाव देता है

ब्राजील ने जैव मिश्रण की सीमा को लगभग 18% से बढाकर 27.3% कर दिया है। ब्राजील विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरी ओर यूरोपीय संघ का सुझाव है कि सदस्य देशों का 10 प्रतिशत परिवहन ईंधन, जैव ईंधन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से आना चाहिए।

निष्कर्ष

जैव ईंधन एक उज्ज्वल भविष्य को रोकता है और इसलिए इस पर काम करने की आवश्यकता है? इस संबंध में प्रौद्योगिकी का विस्तार, एक अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने में सहायता कर सकता है और इस तरह भारत को जैव ईंधन के निर्यातक के रूप में विकसित होने में सहायता कर सकता है।

2 पर्यावरण मंत्रालय का ई-कचरा

चर्चा में क्यों-

हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें उपभोक्ता सामान कंपनियों और इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कचरे का कम से कम 60% एकत्र किया जाए और 2023 तक 2024 और 2025 में उन्हें क्रमशः 70% और 80% तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पुनर्नवीनीकरण किया जाए। अधिसूचना में लैपटॉप, लैंडलाइन और मोबाइल फोन, कैमरा, रिकॉर्डर, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर और चिकित्सा उपकरण सहित इलेक्ट्रॉनिक सामानों की एक विस्तृत श्रृंखला को निर्दिष्ट किया गया है।

जनता से प्रतिक्रिया

भारत दक्षिण एशियाई देशों में अद्वितीय है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन के लिए नियमों का एक औपचारिक सेट है, पहली बार 2016 में इन नियमों की घोषणा की और 2018 में उन्हें संशोधित किया।

यह नवीनतम नियम, जिन्हें जनता की प्रतिक्रिया के लिए रखा गया है, अगस्त तक लागू होने की उम्मीद है। लक्ष्य निर्दिष्ट करने के साथ, नियम विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) प्रमाणपत्र हासिल करने वाली कंपनियों के लिए एक प्रणाली तैयार करते हैं। ये प्रमाण पत्र एक कंपनी द्वारा एक विशेष वर्ष में एकत्रित और पुनर्नवीनीकरण किए गए ई-कचरे की मात्रा को प्रमाणित करते हैं और एक संगठन अपने दायित्वों को पूरा करने में मदद करने के लिए किसी अन्य कंपनी को अधिशेष मात्रा बेच सकता है। पहले के नियमों में संग्रह लक्ष्यों पर जोर दिया गया था। अब सरकार ईपीआर, रीसाइक्लिंग और ट्रेडिंग पर जोर दे रही है। यह सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के सरकार के उद्देश्य का अनुसरण करता है।

कंपनियों को एक ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और अपने वार्षिक उत्पादन और ई-कचरा संग्रह लक्ष्य निर्दिष्ट करना होगा। मुख्य इकाई जो ईपीआर प्रमाणपत्रों के व्यापार का समन्वय करेगी और निगरानी करेगी कि कंपनियां अपने लक्ष्यों को पूरा कर रही हैं या नहीं।

देरी से निपटना

विशेष रूप से, सीपीसीबी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक संचालन समिति इन विनियमों के समग्र कार्यान्वयन की देखरेख करेगी। जो कंपनियां अपने वार्षिक लक्ष्यों को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें जुर्माना या ''पर्यावरण ीय मुआवजा'' देना होगा, लेकिन मसौदा इन जुर्माने की मात्रा को निर्दिष्ट नहीं करता है। वास्तव में, जो कंपनियां कम पड़ती हैं, वे तीन साल बाद भी एक साल के लक्ष्य को पूरा कर सकती हैं। एक साल की देरी से अपने लक्ष्य को पूरा करने वालों को उनका 85% वापस कर दिया जाएगा और दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद क्रमशः 60 प्रतिशत और 30 प्रतिशत जुर्माना का भी प्रावधान है। यह 2017-18 में 10% रीसाइक्लिंग दर थी जो 2018-19 में 20% से थोड़ा अधिक हो गया। ईपीआर के लिए उत्पादकों को संग्रह और पुनर्चक्रण की सुविधा के लिए ई-कचरा वि. निमय सुविधाएं स्थापित करने और सुरक्षित निपटान के लिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के थोक उपभोक्ताओं को विशिष्ट जिम्मेदारी सौंपने की आवश्यकता है।

राज्य सरकारों को ई-कचरे के निराकरण और पुनर्चक्रण सुविधाओं के लिए औद्योगिक स्थ. ान निर्धारित करने, औद्योगिक कौशल विकास करने और ई-कचरे के निराकरण और पुनर्चक्रण सुविधाओं में लगे श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की सुरक्षा के उपाय स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में उत्पादित ई-कचरा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के अनुमान से कम है। ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2017 के अनुसार, भारत सालाना लगभग 2 मिलियन टन (एमटी) ई-कचरा उत्पन्न करता है और अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद ई-कचरा उत्पादक देशों में पांचवें स्थान पर है।

भारत के अधिकांश ई-कचरे को अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा और खतरनाक परिस्थितियों में पुनर्चक्रित किया जाता है और ई-कचरे के नए नियम औपचारिक क्षेत्र के प्रबंधन पर जोर देते है।

NOTES

विज्ञान एवं तकनीक

1 फंगल एक्सट्रैक्ट से प्राप्त बायोमटेरियल, घावों को ठीक करने में सहायक

चर्चा में क्यों?

वैज्ञानिकों ने एक नया बायोमटेरियल विकसित किया है जिसका उपयोग घावों को कीटाणुरहित करने और उपचार की प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया जा सकता है।

नूतन बायोमटेरियल के बारे में:

- बायोमटेरियल पॉलीमर पुलुलन से प्राप्त होता है जो फंगस ऑरियोबैसिडियम पुलुलन द्वारा स्रावित होता है।
- यह एक एक्सोपॉलीसेकेराइड है, अर्थात यह बहुलक कवक द्वारा स्वयं उस माध्यम में स्रावित होता है जिसमें यह बढ़ रहा है।
- पुलुलान एक बायोमटेरियल के रूप में पहले से ही सफल है और व्यापक रूप से व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है।
- इसके गैर-विषैले, गैर-म्यूटाजेनिक और गैर-इम्यूनोजेनिक गुणों के कारण भोजन, सौंदर्य प्रसाधन और दवा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है।
- इसके अलावा, इसके निर्माण में आसानी ने भी इसके उपयोग को बढाया है।
- बायोमेडिसिन क्षेत्र में, इसका उपयोग दवा और जीन वितरण के लिए किया गया है, लेकिन रोगाणुरोधी जैव सामग्री के रूप में इसके उपयोग की खोज नहीं की गई है।

बायोमटेरियल कैसे काम करता है?

- पुलुलन मूल रूप से ग्लूकोज की एक बहुलक श्रृंखला है। बहुलक की जैव-संगत कार्बोहाइड्रेट रीढ़ को बरकरार रखा जाता है और कुछ चतुर्धातुक अमोनियम समूहों को बहुलक में सकारात्मक रूप से चार्ज करने के लिए पेश किया जाता है।
- पॉलिमर को पानी में घुलनशील पाउडर प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। इस घोल को घाव की सतह पर लगाया जाता है और फिर स्टेराइल गौज से ढक दिया जाता है। इसका उपयोग जेल के रूप में भी किया जा सकता है।
- इस बायोमटेरियल का उपयोग करके हाइड्रोजेल-आधारित ड्रेसिंग डिजाइन करना सबसे अच्छा तरीका होगा।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजेल में ऑक्सीजन के आसान आदान-प्रदान के लिए, घावों को एक बंद और नम वातावरण प्रदान करके, घाव भरने में तेजी लाने की एक अंतर्निहित क्षमता होती है और मवाद को हटाने के लिए एक शोषक पैड के रूप में कार्य करती है।

जैव सामग्री की प्रभावकारिता:

- चूहों के घाव पर इसे सीधे लगा कर सामग्री की प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया।
- घाव कीटाणुरहित हो गया और उपचार भी तेज हो गया।
- जैव सामग्री 12 दिनों के भीतर घावों को 100% ठीक कर सकती है, जबकि जैव-सामग्री ना लगाने पर, क्लोजर केवल 60% था।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, सात दिनों के भीतर, बालों के रोम के साथ-साथ घाव के किनारों से अच्छी तरह से जुड़ी एक मोटी नव-एपिथेलियल परत बन गई थी।
- एपिथेलियल परत के नीचे अधिक बालों के रोम के साथ पूरी तरह से ठीक हुई त्वचा और घनी पैक्ड कोलेजन 12वें दिन तक देखी गई।

निष्कर्ष:

- इस सामग्री का उपयोग करके चिकित्सा प्रत्यारोपण के लिए जीवाणुरोधी कोटिंग्स का विकास किया जा रहा है।
- इन कोटिंग्स की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए पशु मॉडल में परीक्षण चल रहा है।
- इस बायोमटेरियल का उपयोग करके हाइड्रोजेल-आधारित घाव ड्रेसिंग डिजाइन करना सबसे अच्छा तरीका है।

NOTES

2 मंकीपॉक्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में स्वास्थ्य अधिकारियों ने नाइजीरिया से उस देश की यात्रा करने वाले व्यक्ति में चेचक के समान एक दुर्लभ वायरल संक्रमण, मंकीपॉक्स के एक मामले की पुष्टि की है।

मंकीपॉक्स वायरस क्या है?

मंकीपॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है, जो वायरस की एक जाति का है जिसमें वेरियोला वायरस भी शामिल है, जो चेचक का कारण बनता है और वैक्सीन वायरस, जिसका उपयोग चेचक के टीके में किया जाता था जबकि टीकाकरण ने 1980 में दुनिया भर में चेचक का उन्मूलन कर दिया था।

मध्य और पश्चिम अफ्रीका के देशों में मंकीपॉक्स का प्रकोप जारी है और कभी-कभी यह कहीं और दिखाई देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, दो अलग.-अलग समूहों की पहचान की गई है: पश्चिम अफ्रीकी क्लैड और कांगो बेसिन क्लैड, जिसे सेंट्रल अफ्रीकी क्लैड भी कहा जाता है।

यह कैसे संचारित होता है?

मंकीपॉक्स एक जूनोटिक रोग है क्योंकि यह संक्रमित जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, वायरस को फैलाने वालें जानवर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाते हैं। गिलहरी, गैम्बियन शिकार चूहों, डॉर्मिस और बंदरों की कुछ प्रजातियों में मंकीपॉक्स वायरस के संक्रमण का पता चला है।

इसका मानव-से-मानव संचरण सीमित है। संचरण शारीरिक संपर्क के माध्यम से, त्वचा पर घाव या आंतरिक म्यूकोसल सतहों पर (जैसे कि मुंह या गले में), श्वसन की बूंदों और दूषित वस्तुओं के माध्यम से हो सकता है।

लक्षण और उपचार

मंकीपॉक्स के लक्षण चेचक के समान होते हैं, हालांकि वे कम गंभीर होते हैं। इसकी शुरुआत बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द और थकावट से होती है। यह लिम्फ नोड्स में सूजन (लिम्फैडेनोपैथी) का कारण बनता है, जो चेचक नहीं करता है।

मंकीपॉक्स की अवधि आमतौर पर 7-14 दिन होती है लेकिन यह 5-21 दिनों तक हो सकती है। आमतौर पर बुखार शुरू होने के 1 दिन से 3 दिनों के अंदर रोगी के चेहरे दाने आना शुरू होते है जो शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है। त्वचा के फटने की अवस्था 2 से 4 सप्ताह के बीच रह सकती है, जिसके दौरान घाव सख्त हो जाते हैं और दर्दनाक हो जाते हैं, पहले वह तरल पदार्थ से भर जाते हैं और फिर मवाद और फिर पपड़ी विकसित हो जाती है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, मरने वाले रोगियों का अनुपात 0 से 11% के बीच होता है और छोटे बच्चों में यह अधिक होता है।

मंकीपॉक्स का अभी तक कोई सुरक्षित, प्रमाणित इलाज नहीं है। डब्ल्यूएचओ लक्षणों के आधार पर सहायक उपचार की सिफारिश करता है। संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जागरूकता जरूरी है।

रोग का इतिहास

सीडीसी के मंकीपॉक्स के बारे में कहा गया है कि संक्रमण का पता पहली बार 1958 में लगा था, जब शोध के लिए रखे गए बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के दो प्रकोप हुए थे, जिसके कारण इसका नाम श्मंकीपॉक्सश पड़ा। पहला मानव मामला 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) में चेचक को खत्म करने के तीव्र प्रयास की अवधि के दौरान दर्ज किया गया था।

NOTES

आर्थिक

1 राष्ट्रीय कोल्ड चेन सिस्टम और भविष्य की महामारी के लिए भारत की तैयारी

हेल्थकेयर सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं की श्रृंखला है, विभिन्न टीमों में शामिल कार्यबल और दवाओं, सर्जिकल उपकरण और अन्य उत्पादों की आपूर्ति, जैसा कि स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा अपना काम करने के लिए आवश्यक है। महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम सभी वेरिएंट, वेव्स, वैक्सीन सप्लाई चेन और क्वारंटाइन जैसे शब्दों से परिचित हो गए हैं। इसने पुनर्मूल्यांकन और

पुनर्गठन के लिए भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को भी विकसित किया है।

भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी):-

सभी जरूरतमंदों तक टीका पहुँचाने के लिए, 1985 में टीकाकरण के लिए भारत का यूआईपी लॉन्च किया गया, जिसने बड़े पैमाने पर वैक्सीन वितरण के प्रबंधन में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य वार्षिक रूप से, लगभग 2.67 करोड़ नवजात शिशु और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना था ।

2014 में टीकाकरण कार्यक्रम के प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए, मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत की गई ताकि सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पूर्ण टीकाकरण कवरेज को तीव्र गति से पूर्ण किया जा सके। कोविड महामारी ने हमें सबक सिखाया है कि केवल वैक्सीन से जान नहीं बचाई जा सकती, टीकाकरण से ही बचाव संभव है। हमने वर्षों से एक मजबूत वितरण नेटवर्क स्थापित किया है, महामारी ने हमें दिखाया कि उस श्रृंखला में कुछ कमजोर लिंक (जैसे- कोल्ड चेन के कुप्रबंधन की चुनौती) थे, जिसे सुधारने और मजबूत करने की आवश्यकता है।

शीत श्रृंखला प्रबंधन:

किसी भी स्थायी टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है:-

1. एक प्रमुख कारक कोल्ड चेन प्रबंधन है जिसमें टीके की शक्ति या प्रभावशीलता निहित होती है। विश्व के बड़े हिस्से में भंडारण तापमान को ठीक से नियंत्रित करने में विफलता के कारण, दुनिया भर में वितरित लगभग आधे टीके बेकार हो जाते हैं।
2. भारत में, लगभग 20% तापमान संवेदनशील स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद (हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स, जिसमें एक चौथाई टीके शामिल हैं), कमजोर और अपर्याप्त कोल्ड चेन के कारण क्षतिग्रस्त या खराब हो जाते हैं।
3. कोविड-19 टीकाकरण के प्रयास यूआईपी के तहत स्थापित कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर थे, जिसमें 87 करोड़ लोगों को टीके की दो खुराक और 100 करोड़ से अधिक लोगों को कम से कम एकल खुराक के साथ कवर किया गया था।

वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क का डिजिटलीकरण -

स्वास्थ्य मंत्रालय हाल के वर्षों में ई-विन (इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क) जैसी क्लाउड तकनीक के उपयोग के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क का डिजिटलीकरण कर रहा है। गावी, वैक्सीन एलायंस के समर्थन से विकसित और स्मार्ट फोन आधारित ऐप के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा लागू किया गया है, यह प्लेटफॉर्म देश भर में वैक्सीन स्टॉक और अस्थायी जानकारी को डिजिटाइज करता है। इस संबंध में, विशेष रूप से विद्युतीकरण में सुधार करने की आवश्यकता है, जिसके लिए सतत विकास को एकीकृत करने के लिए सौर-प्रौद्योगिकी की क्षमता का पता लगाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ में नियमित बि. जली कटौती के मुद्दे से निपटने के लिए 72 % कार्यरत स्वास्थ्य केंद्रों को सोलराइज (सौर ऊर्जा से संचालित) किया गया है। जैसा कि हम महामारी से मिली सीखों पर चिं. तन करते हैं यह अनिवार्य हो जाता है कि हम एक ऐसे भविष्य की ओर देखें जहां महत्वपूर्ण श्रंखलाओं को मजबूत किया जाए, जिसमें टीकाकरण सुविधाओं की आपूर्ति श्रृंखला शा. मिल है।

कोल्ड चेन में सुधार लाने वाली कार्रवाई योग्य नीतियों की दिशा में कदम उठाकर, हमारे पास बेहतर और मजबूत निर्माण के मार्ग का नेतृत्व करने का अवसर है।

NOTES

2 आईएमएफ ने भारत के विकास पूर्वानुमान को 8.2% तक घटाया

निजी तौर पर आयोजित एक प्रौद्योगिकी स्टार्टअप जिसका मूल्यांकन 1 बिलियन डॉलर (लगभग 7,500 करोड़) से अधिक है, 2013 में एक अमेरिकी एंजेल निवेशक एलेन ली द्वारा ऐसे स्टार्टअप के लिए 'यूनिकॉर्न' शब्द, गढ़ा गया था, उस समय भारत में एक भी 'यूनिकॉर्न' नहीं था। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट (2021) के अनुसार एक दशक की इस छोटी अवधि में,भारत स्वदेशी रूप से निर्मित 100 'यूनिकॉर्न' की मेजबानी कर रहा है। 20वीं सदी के अंत में, भारत ने विश्व का सॉफ्टवेयर हब होने की ख्याति प्राप्त की थी। इसने एक तकनीकी क्रांति की शुरुआत की, जिसके परिणामस्वरूप कई भारतीय स्टार्टअप का विकास हुआ, जिसमें अत्याधुनिक तकनीकों के नवाचार भी शामिल थे। जल्द ही, इनमें से कुछ स्टार्टअप विकसित होकर यूनिकॉर्न बन गए। यूनिकॉर्न की संख्या की बात करें तो भारत इस मामले में, अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है।

भारत को यूनिकॉर्न गंतव्य बनाने के कारण

1. **अनुकूल जनसांख्यिकी:** मात्र 29 वर्ष की औसत आयु के साथ, दुनिया का सबसे युवा देश होने के नाते, भारत में उद्यमिता की असीम संभावनाएं हैं-

- कुशल जनशक्ति और प्रौद्योगिकी सुधार की स्वीकार्यता।
- एक बेहतर जीवन शैली की इच्छा।
- तकनीक-प्रेमी ग्राहक की उपलब्धता।
- कम आयु वर्ग के कारण बढ़ती आकांक्षा, एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है।

2. **स्टार्टअप इकोसिस्टम:** स्टार्टअप गंतव्य के रूप में भारत के उदय में, प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकारी प्रयासों के साथ बढ़ते बढ़ते बुनियादी ढाँचे के विकास ने, बेंगलुरु को भारत की सॉफ्टवेयर राजधानी के रूप में विकसित किया है जो एक स्टार्ट-अप राजधानी भी है। मुंबई और दिल्ली भी इस दिशा में, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

3. **सरकार उपशमन :** जब 2016 में विमुद्रीकरण आया, तो यह स्टार्टअप्स, विशेष रूप से फिनटेक के लिए एक वरदान साबित हुआ। डिजिटल भुगतान कंपनियों के उदय ने पहले के महत्वहीन बाजार के लिए परिदृश्य बदल दिया है।

'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहल ने स्थानीय उद्यमियों को जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। महामारी के दौरान सरकार द्वारा बड़ा समर्थन और सहयोग प्रदान किया गया, जिससे भारत की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में भारी सुधार हुआ है। भारत 17 पायदान चढ़ कर, 63 वें स्थान पर पहुँच गया है।

4. **इंटरनेट और अन्य प्रौद्योगिकियां :** इंटरनेट ने व्यवसायों के संचालन के तरीके को बदल दिया है और ग्राहक अपने दैनिक जीवन का नेतृत्व करते हैं। सबसे सस्ती दर पर उपलब्ध डेटा, स्मार्टफोन के उपयोग और स्थानीय भाषा की सामग्री की उपलब्धता ने भारत के लिए प्रौद्योगिकी में नवाचार करने के बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं। ई-कॉमर्स का निर्माण विशुद्ध रूप से पूरे भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने का सुपरिणाम है।

5. **ग्राहकों की पसंद बदलना:** स्टार्टअप्स ने अपने मूल व्यवसाय की श्रेणी को पछाड़ दिया है और दिग्गज बनने की ख्वाहिश रखते हैं। जैसा कि फ्लिपकार्ट ने एक बुकसेलर के रूप में शुरुआत की थी और आज वो एक प्रमुख ई-कॉमर्स खिलाड़ी है। इसी तरह पेटीएम एक डिजिटल वॉलेट के रूप में शुरू हुआ था लेकिन आज सुपर ऐप बनने की ख्वाहिश रखता है।

चुनौतियाँ

- **टिकाऊ बिजनेस मॉडल का अभाव:** यूनिकॉर्न बनना मुश्किल था लेकिन कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच वहां बने रहना और भी मुश्किल है। अधिकांश स्टार्ट-अप (यहां तक कि यूनिकॉर्न भी) घाटे में चल रहे उद्यम हैं। उदाहरण- जोमैटो , उबर आदि।
- **वेंचर कैपिटल के पैसे पर निर्भरता, स्टार्ट-अप जो अंततः** यूनिकॉर्न बन जाते हैं, ज्यादातर वीसी के पैसे से वित्त पोषित होते हैं। (उद्यम पूँजीपतियों)। अधिकांश वेंचर्स घाटे में हैं इसलिए अगर वीसी द्वारा फंडिंग बंद हो जाती है तो इन स्टार्टअप्स के सामने जीवन और मृत्यु का सवाल आता है।
- पारंपरिक कंपनियों का परिवर्तन: पारंपरिक व्यवसायों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा उनके अस्तित्व के लिए खतरों को कम कर देगी। फोन-पे और गूगल पे एक साथ रिटेल डिजिटल पेमेंट स्पेस में वॉल्यूम (86%) और वैल्यू (80%) पर हावी हैं, लेकिन श्रपव सुपर ऐप और टाटा नियो सुपर ऐप उनके अस्तित्व को चुनौती देंगे।

फोन-पे और गूगल पे एक साथ रिटेल डिजिटल पेमेंट स्पेस में वॉल्यूम (86%) और वैल्यू (80%) पर हावी हैं, लेकिन श्रपव सुपर ऐप और टाटा नियो सुपर ऐप उनके अस्तित्व को चुनौती देंगे।

- इसलिए भारत में यूनिकॉर्न या स्टार्टअप क्षेत्र में भविष्य के एमएनसीएस बनने और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भारत को आगे बढ़ाने की क्षमता है। लेकिन कुछ चुनौतियाँ ऐसी हैं जो सकारात्मक परिणामों में बाधक बन सकती हैं।

NOTES

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें

1. क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी

पांच व्यापक विषय क्षेत्रों में समूहित कुल 51 विषयों के लिए उच्च शिक्षा थिंक-टैंक क्यूएस क्वाक्वेरेली साइमंड्स ने 'क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2022' जारी की है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने कला और मानविकी स्ट्रीम में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कला और मानविकी क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को 188वां स्थान मिला है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को पहला स्थान मिला है। इस क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली को क्रमशः 65वां और 72वां रैंक मिला है। जीवन विज्ञान और चिकित्सा में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को 204 वें स्थान पर रखा गया है जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय को 330 वां स्थान मिला है। हार्वर्ड यूनिवर्सि. टी ने जीवन विज्ञान और चिकित्सा और सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट स्ट्रीम में पहला स्थान प्राप्त किया है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 12 विषयों में पहला स्थान हासिल किया है।

2. अमर मित्र को ओ.हेनरी पुरस्कार

अमर मित्र को उनकी लघु कहानी, "द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर" के लिए प्रतिष्ठित ओ.हेनरी पुरस्कार मिला है। किताब मूल रूप से बंगाली में "गांबुरो" शीर्षक से लिखी गई थी। उनकी इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद वरिष्ठ पत्रकार अनीश गुप्ता ने किया है जिसे पिछले साल वेब पत्रिका द कमान में प्रकाशित किया गया था। अमर मित्र को यह पुरस्कार 20 विजेताओं के साथ दिया गया है। गांबुरो अमर मित्र द्वारा 1977 में बंगाली में लिखा गया था और अमृता पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। वरिष्ठ पत्रकार अनीश गुप्ता ने इस कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसे पिछले साल वेब पत्रिका 'द कॉमन' में प्रकाशित किया गया था। इससे पहले अमर मित्र को बंकिम पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है।

ओ. हेनरी पुरस्कार एक नजर में

यह पुरस्कार लघु कथाओं के लिए दिया जाता है। यह केवल उन लेखकों को प्रदान किया जाता है जिनकी लघु कथाएं कनाडा और अमेरिका में प्रकाशित हुई हैं। 1919 से यह प्रशंसित लेखक ओ हेनरी की स्मृति में दिया जा रहा है।

3. सेमीकंडक्टर मिशन के लिए मंत्रालय ने सलाहकार समिति गठित

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सेमीकंडक्टर मिशन के लिए एक 17 सदस्यीय समित का गठन किया है। इस 17 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। वहीं राजीव चंद्रशेखर इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे। नीति आयोग के सदस्य वी के सारस्वत, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और विभिन्न विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य होंगे। समिति सरकार को एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ बौद्धिक संपदा सृजन के लिए इनपुट देगी। समिति स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए एक इकोसिस्टम विकसित करने के लिए सुझाव देगी। बता दें कि पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी थी।

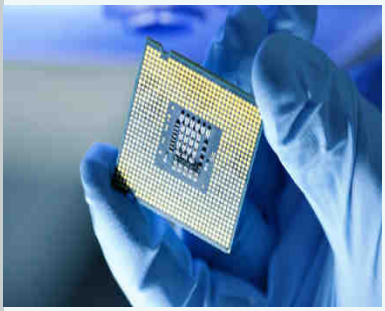

4. ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 जारी

वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद ने ग्लोबल विंड रिपोर्ट-2022 जारी की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्तमान समय में पवन ऊर्जा की कुल क्षमता बढ़कर 837 गीगावॉट हो गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2021 में स्थापित पवन ऊर्जा 2020 में स्थापित पवन ऊर्जा से कम थी। 2021 में 93.6 गीगावाट पवन क्षमता स्थापित की गई है, जो 2020 में स्थापित 95.3 गीग. ावाट से कम है। रिपोर्ट में यह भी बतया गया है कि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में पवन स्थापना क्षमता में कमी आई है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 2050 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पवन स्थापना क्षमता को एक दशक में चौगुना किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में भारत के सन्दर्भ में कहा गया है कि 2021 में भारत ने 1.45 GW पवन क्षमता जोड़ी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30% अधिक है। भारत की पवन क्षमता स्थापना दर अप्रैल से मध्य जून 2021 के बीच धीमी हो गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत एक उचित पुनर्शक्ति नीति के माध्यम से पुराने KW-रेटेड पवन टर्बाइनों को फिर से चालू करके पवन क्षमता को और बढ़ा सकता है।

5. एसएफडीआर बूस्टर का डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण

सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (एसएफडीआर) बूस्टर का ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर में सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। एसएफडीआर-आधारित प्रपल्शन मिसाइलों को सुपरसोनिक गति (1 मैक से अधिक) से बहुत लंबी दूरी पर हवाई खतरों को रोकने में सक्षम बनाता है। इस तकनीक का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद ने अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं (यथा अनुसंधान केंद्र इमारत, हैदराबाद और उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, पुणे) के साथ मिलकर किया है।

6. फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी

कैबिनेट ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल वितरित करने को मंजूरी दे दी है। फोर्टिफाइड चावल को एकीकृत बाल विकास सेवाओं, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण-पीएम पोषण और अन्य कल्याण योजनाओं के माध्यम से भी वितरित किया जाएगा। यह पहल तीन चरणों में लागू की जाएगी। ''सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल का फोर्टिफिकेशन और उसका वितरण'' पर एक पायलट योजना 2019-20 में लागू की गई थी। भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों ने आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित करने के लिए पहले ही 88 एलएमटी फोर्टिफाइड चावल खरीद ली है। चावल के फोर्टिफिकेशन की कुल लागत केंद्र वहन करेगा। देश में कुपोषण को कम करने के लिए फोर्टिफाइड चावल गरीब लोगों, महिलाओं, बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं को लाभ प्रदान करेगा। फोर्टीफिकेशन खाद्य पदार्थों में आयरन, आयोडीन, जिंक और विटामिन ए और डी जैसे प्रमुख विटामिन और खनिजों का समावेश होता है।

7. 'गीतांजलि श्री' को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार

अपनी पुस्तक 'रेत का मकबरा' के लिए गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2022 पुरस्कार दिया गया है। यह पहला अवसर है जब किसी भारतीय भाषा के लेखक को यह पुरस्कार मिला है। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने 'टॉम्ब ऑफ सैंड' के नाम से किया है। उपन्यास की कहानी एक 80 वर्षीय महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने पति की मृत्यु के बाद अवसाद में चली जाती है। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की गीतांजलि ने अब तक तीन उपन्यासों की रचना की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई रचनाओं का अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, सर्बियाई और कोरियाई में अनुवाद किया है। ब्रिटेन में प्रकाशित होने वाली उनकी पहली किताब होगी। बता दें कि डेविड डियोप को उनकी पुस्तक ''एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक'' के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार एक नजर में :-

पहले इस पुरस्कार को मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। यह पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक के लिए दिया जाता है। खास बात है कि पुरस्कार राशि लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से बांटी जाती है।

8. तमिलनाडु के वाद्ययंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया

डीआरडीओ ने पिनाका एमके-I (उन्नत) रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डेनियल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। पिनाका रॉकेट प्रणाली को डीआरडीओ की पुणे प्रयोगशाला के आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है। बता दें कि परीक्षण के दौरान रॉकेटों द्वारा अपेक्षित सटीकता और स्थिरता हासिल की गई है। ईपीआरएस पिनाका संस्करण का उन्नत संस्करण है जो उभरती आवश्यकताओं को पूरा करेगा। पिनाका रॉकेट सिस्टम प्रौद्योगिकी के उन्नत संस्करण को म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड नागपुर जैसे रक्षा उद्योगों को स्थानांतरित किया गया है। बता दें कि पिनाका रॉकेट सिस्टम 44 सेकेंड में 12 रॉकेट दाग सकती है।

9. संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप और संगीत नाटक पुरस्कार प्रदान किए गए

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटी अकादमी फैलोशिप और संगीत नाटक पुरूस्कार प्रदान किये। उन्होंने इसी समरोह में प्रतिष्ठित कलाकारों को ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया। चार कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप से सम्मानित किया गया है और 40 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीन कलाकारों सहित 23 हस्तियों को ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला। तबला वादक जाकिर हुसैन, जतिन गोस्वामी, डॉ. सोनल मानसिंह और थिरुविदैमरुदुर कुप्पिया कल्याणसुंदरम को संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप से सम्मानित किया गया। वहीं हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट और श्याम शर्मा को ललित कला अकादमी की प्रतिष्ठित फैलोशिप से सम्मानित किया गया है।

संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एक नजर में :

संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अभ्यास करने वाले कलाकारों को दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1952 में प्रदान किया गया था। संगीत नाटक अकादमी प्रख्यात कलाकारों और संगीत, नृत्य और नाटक के विद्वानों को फैलोशिप भी प्रदान करती है।

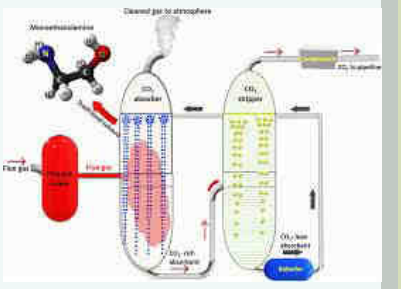

10. कार्बन कैप्चर के लिए हाइब्रिड सामग्री और प्रक्रिया

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी (आईआईसीटी), हैदराबाद के वैज्ञानिकों के एक समूह ने एक हाइब्रिड सामग्री तैयार की है जो ग्रीनहाउस गैस मीथेन को अवशोषित कर सकती है। वैज्ञानिकों ने ऐसी सामग्री के परीक्षण के लिए एक ऐसा मैकनिस्म तैयार किया है जो कार्बन कैप्चर से संबंधित शोध में मदद करेगा। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने और उसको उच्च शुद्धता वाले हाइड्रोजन में इसके रूपांतरण के लिए एक प्रक्रिया तैयार की है। इस शोध को एल्सेवियर जर्नल केमिकल इंजीनियरिंग और प्रोसेसिंग में प्रकाशित किया गया है। मिशन इनोवेशन प्रोजेक्ट के तहत, हाल ही में सीएसआईआर-आईआईसीटी, हैदराबाद में फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर सिस्टम (एफबीआर) सुविधा शुरू की गई है। यह फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर सिस्टम (एफबीआर) में एसईएसएमआर के लिए दोहरी कार्यात्मक सामग्री के प्रदर्शन का परीक्षण करने में मदद करेगा।

11. थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत को स्वर्ण पदक

थाईलैंड के फुकेत में 2022 के थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत के तीन मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता है। इन तीन भारतीयों के नाम गोविंद साहनी, अनंत चा. ेपडे और सुमित हैं। इसी प्रतियोगिता में अन्य चार भारतीय मुक्केबाजों मोनिका, अमित पंघ. ाल, वरिंदर सिंह और आशीष कुमार ने रजत पदक जीते हैं। जबकि मनीषा, पूजा और भ. ाग्यबती कचारी ने कांस्य पदक जीते। इस मुक्केबाजी प्रतियोगिता में15 सदस्यीय भारतीय दल ने कुल 10 पदक जीते। पदक जीतने वाले खिलाडियों की तालिका नीचे दी हुई है।

2022 थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट

स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक
गोविंद साहनी	मोनिका	मनीषा
अनंत चोपडे	अमित पंघाल	पूजा
सुमित	वरिंदर सिंह आशीष कुमार	भाग्यबती कचारी

12. एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड प्रणाली को लागू करने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC) प्रणाली को लागू करने का निर्देश दिया, जो 31 जुलाई 2021 तक अंत: तथा अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी की अनुमति देता है। ONORC योजना का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से रियायती राशन खरीदने में सक्षम बनाना है।

ONORC ऐसी तकनीक पर आधारित है जिसमें लाभार्थियों के राशन कार्ड, आधार संख्या और इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ePoS) का विवरण शामिल है। यह प्रणाली उचित मूल्य की दुकानों पर ईपीओएस उपकरणों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से लाभार्थी की पहचान करती है। यह सिस्टम दो पोर्टलों के समर्थन से चलता है- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन, (IM&PDS) और अन्नवितरण (annavitran-nic-in) जो सभी प्रासंगिक डेटा को होस्ट करता है।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

- यूएस सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनीं केतनजी ब्राउन जैक्सन। यूएस सुप्रीम कोर्ट के 233 साल के इतिहास में 115 जस्टिस में से 108 गोरे लोग रहे हैं।
- विनोद राय की 'नॉट जस्ट ए नाइटवॉचमैन: माई इनिंग्स विद बीसीसीआई' नामक पुस्तक लॉन्च की गई। इसके अलावा ''नॉट जस्ट ए अकाउंटेंट: द डायरी ऑफ द नेशन्स कॉन्शियस कीपर'' और ''रीथिंकिंग गुड गवर्नेंस: होल्डिंग टू अकाउंट इंडियाज पब्लिक इंस्टीट्यूशंस'' उनकी कुछ अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। बता दें कि विनोद राय भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) हैं।
- भारत ने विश्व युगल स्क्वैश चौंपियनशिप में अपना पहला महिला युगल और मिश्रित युगल खिताब जीता। दीपिका पल्लीकल ने सौरव घोषाल और जोशना चिनप्पा के साथ मिलकर ग्लासगो में विश्व युगल स्क्वैश चौंपियनशिप में मिश्रित युगल और महिला युगल खिताब जीता है।
- स्पेस-एक्स ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी मिशन लॉन्च किया। चार लोगों को लेकर क्रू ड्रैगन कैप्सूल के साथ स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। माइकल लोपेज-एलेग्रिया, नासा के एक सेवानिवृत्त अंतरिक्ष यात्री, चालक दल का नेतृत्व कर रहे हैं।
- इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना। इक्वाडोर की सर्वोच्च अदालत ने ऊनी बंदर एस्ट्रेलिटा के मामले की सुनवाई करते हुए अधिकारों को मान्यता देने का फैसला किया। बता दें कि बोलीविया, न्यूजीलैंड, पनामा, चिली, मैक्सिको, कोलंबिया और बांग्लादेश ने भी प्रकृति के अधिकारों को मान्यता दी है।
- नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक (SECI)-राउंड I जारी किया। इस सूचकांक के तहत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है: फ्रंट रनर, अचीवर्स और एस्पिरेंट्स। बड़े राज्यों की श्रेणी में, गुजरात, केरल और पंजाब शीर्ष तीन प्रदर्शनकर्ता हैं। गोवा, छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा, इसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर का स्थान है। केंद्र शासित प्रदेशों में, चंडीगढ़, दिल्ली और दमन और दीव/दादरा और नगर हवेली शीर्ष प्रदर्शनकर्ता हैं।
- भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैलीना का सफल परीक्षण किया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 'हेलीना' का उड़ान परीक्षण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक किया गया। उड़ान परीक्षण संयुक्त रूप से डीआरडीओ, भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना (IAF) द्वारा आयोजित किया गया था। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 'हेलीना' दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है।
- जमशेदपुर ने पहले खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी की। टूर्नामेंट का पहला चरण 12 और 13 अप्रैल को झारखंड के जमशेदपुर में शुरू किया गया।
- कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी 2023 में भारत करेगा।
- IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना श्कदमश लॉन्च किया है। कदम के हिन्ज-जॉइंट पर फायदे हैं क्योंकि इसमें रोटेशन की कई एक्सिस हैं, और यह अधिकतम घुटने को 160 डिग्री तक मोड़ने की अनुमति देता है जिससे घुटने के ऊपर के एंप्ट्यूट को तंग स्थानों में बैठना आसान हो जाता है। यह एल्यूमीनियम मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील से बना है। यह सस्ता है और उच्च गुणवत्ता और प्रदर्शन का है।
- स्वदेश निर्मित डोर्नियर 228 विमान ने असम से अरुणाचल प्रदेश के लिए अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान भरी।

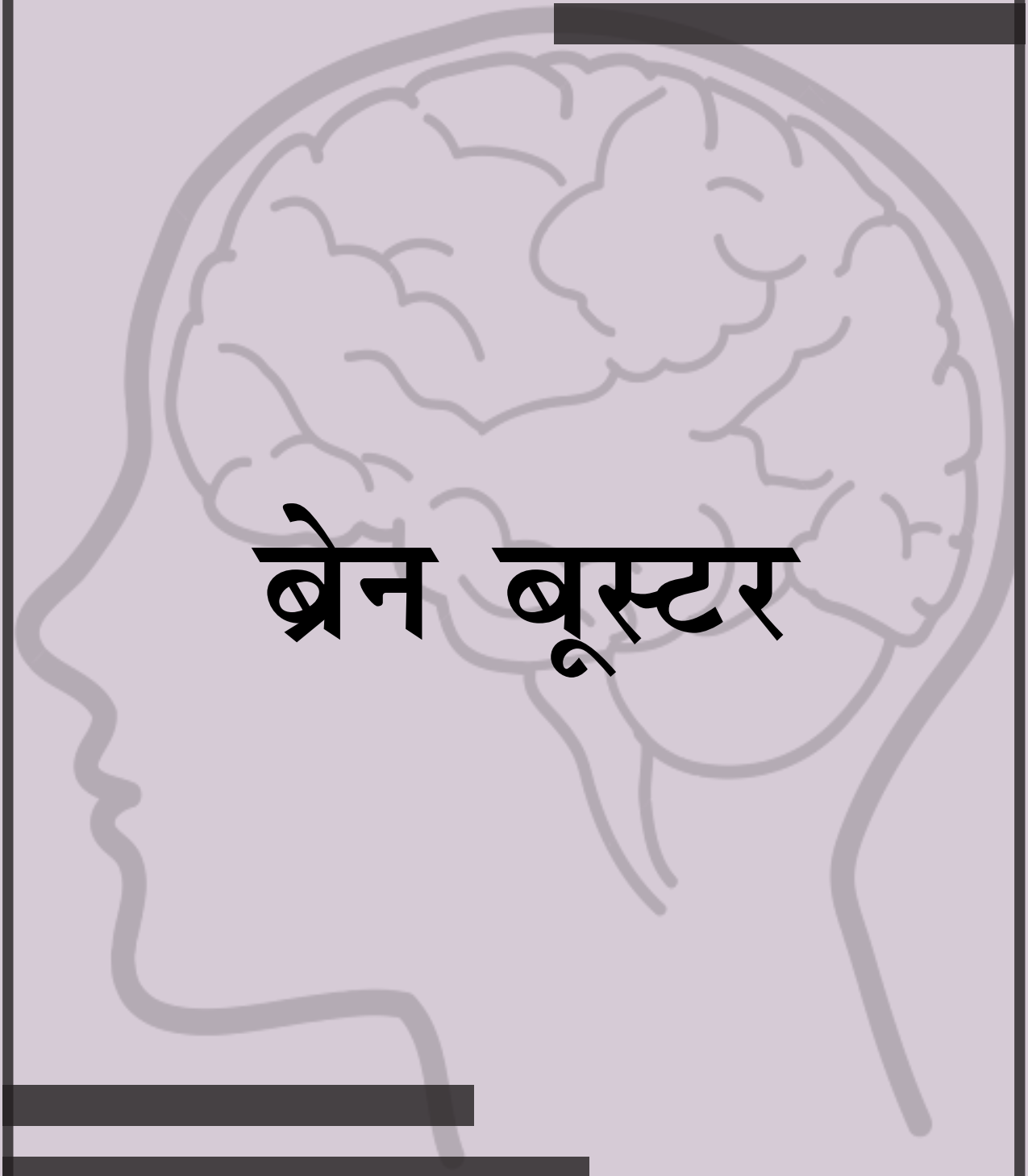

ब्रेन बूस्टर

जम्मू और कश्मीर की झीलें

1. कौसर नाग

- कौसर नाग या कौसरनाग, जम्मू और कश्मीर के कुलगाम जिले में पीर पंजाल रेंज में स्थित एक उच्च ऊंचाई वाली ओलिगोट्रोफिक झील है।
- कौसर नाग की समुद्र तल से ऊंचाई 4,000 मीटर (13,000 फीट) है।

2. वुलर झील

- वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है।
- यह बांदीपोरा/बारामूला जिले में स्थित है।
- झील के बेसिन का निर्माण विवर्तनिक गतिविधि के परिणामस्वरूप हुआ और इसमें झेलम नदी का जल आता है।
- झील एक रामसर साइट है।
- झील के चारों ओर पाए जाने वाले स्थलीय पक्षियों में काले बाज, यूरेशियन स्पैरोहॉक, शॉर्ट-टोड ईगल, हिमालयन गोल्डन ईगल, हिमालयन मोनाल, चुकर पार्ट्रिज, कोकलास तीतर, रॉक डव, कॉमन कोयल, अल्पा. इन स्विफ्ट, इंडियन रोलर, हिमालयन चॉफ, हिमालयन गोल्डन ईगल, सिनामोन स्पैरो और ब्लैक बुलबुल शामिल हैं।

3. तरसर झील

- तरसर झील या तरसर, एक अल्पपोषी अल्पाइन झील, कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले में स्थित है।
- तरसर झील पूर्व में कोलाहोई पर्वत स्थित है।
- झील एक पहाड़ द्वारा उसी प्रकृति की दूसरी झील से अलग होती है जिसे मारसर झील के नाम से जाना जाता है, जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के पास है।
- इन दोनों झीलों को जुड़वा बहनें कहा जाता है।
- तरसर झील से निकास धारा बहती है जो लिद्दरवाट में लिद्दर नदी में गिरती है।
- गर्मियों के दौरान यहां प्रवासी पक्षियों की प्रजनन कॉलोनियां होती हैं, जिनमें बार-हेडेड गीज, लैमर्जियर, हाई-फ्लाइंग
- तरसर का बेसिन और उससे सटे दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर हिरन (हंगुल), आइबेक्स, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, हिमालयी भूरा भालू और ऊंचे इलाकों में गोल्डन मर्मोट के सबसे महत्वपूर्ण आवासों में से एक है।

4 डल झील

- डल झील श्रीनगर में स्थित है (डल का कश्मीरी में अर्थ झील है)।
- शहरी झील, कश्मीर में पर्यटन और मनोरंजन का अभिन्न अंग है और इसे "कश्मीर के ताज में गहना" या "श्रीनगर का गहना" नाम दिया गया है।
- झील मछली पकड़ने और जलीय पौधों के वाणिज्यिक संचालन के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
- झील के मनोरम दृश्य मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल के दौरान बनाए गए शालीमार बाग और निशात बाग जैसे मुगल उद्यानों से और शिकाराओं से देखे जा सकते हैं।
- सर्दी के मौसम में, तापमान -11°C तक पहुंच जाता है, जिससे झील जम जाती है।
- झील 18 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है और एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि का हिस्सा है जो 21.1 वर्ग किलोमीटर को कवर करती है।
- तैरते हुए बगीचे, जिन्हें कश्मीरी में "राड"के नाम से जाना जाता है, जुलाई और अगस्त के दौरान कमल के फूलों से भर जाते हैं।
- आर्द्रभूमि को कार्यमार्गों द्वारा चार घाटियों में विभाजित किया गया है; गगरीबल, लोकट दल, बोड दल और निगीन।
- लोकुट-दल और बोड़-दल में से प्रत्येक के बीच में एक द्वीप है, जिसे क्रमशः रूप-लंक (चार चिनारी) और सोना-लंक के नाम से जाना जाता है।

5. गंगबल

- गंगबल झील, भारत के जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में श्रीनगर शहर के उत्तर में गांदरबल जिले में हरमुख पर्वत की तलहटी में स्थित एक झील है।
- यह एक अल्पाइन उच्च ऊंचाई वाली ओलिगोट्रोफिक झील है, जिसमें ब्राउन ट्राउट सहित मछलियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं।
- यह वर्षा, हिमनदों और झरनों द्वारा पोषित होती है।
- झील का पानी पास की नुंड. कोल झील में और फिर वांगथ नाले से होते हुए सिंधु नदी तक जाता है।

आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है।

आजादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को शुरू हुई, जिसने हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75-सप्ताह की उलटी गिनती शुरू की और 15 अगस्त 2023 को एक वर्ष के बाद समाप्त होगी।

थीम

आजादी का अमृत महोत्सव के पांच थीम हैं:

1. स्वतंत्रता संग्राम

- इतिहास में मील के पत्थर, गुमनाम नायकों आदि को याद करना।
- यह थीम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हमारे स्मरणोत्सव की पहल की एंकर है।
- यह उन गुमनाम नायकों की कहानियों को जीवंत करने में मदद करता है जिनके बलिदान ने हमारे लिए स्वतंत्रता को एक वास्तविकता बना दिया है और 15 अगस्त, 1947 की ऐतिहासिक यात्रा के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों, स्वतंत्रता आंदोलनों आदि की भी समीक्षा करता है।
- इस विषय के तहत कार्यक्रमों में बिरसा मुंडा जयंती (जनजातीय गौरव दिवस), नेताजी द्वारा स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार की घोषणा, शहीद दिवस आदि शामिल हैं।

2. आईडिया@75

- भारत को आकार देने वाले विचारों और आदर्शों का जश्न मनाना।
- यह विषय उन विचारों और आदर्शों से प्रेरित कार्यक्रमों और घटनाओं पर केंद्रित है जिन्होंने हमें आकार दिया है और अमृत काल (भारत@75 और भारत@100 के बीच 25 वर्ष) की इस अवधि के माध्यम से नेविगेट करते समय हमारा मार्गदर्शन करेंगे।
- इस विषय के तहत कार्यक्रमों में लोकप्रिय, सहभागी पहल शामिल हैं जो दुनिया में भारत के अद्वितीय योगदान को जीवंत करने में मदद करती हैं।
- इनमें काशी की भूमि के हिंदी साहित्यकारों को समर्पित काशी उत्सव, प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड, जिसमें 75 लाख
- अधिक बच्चे 2047 में भारत के बारे में अपना दृष्टिकोण लिख रहे हैं, जैसे कार्यक्रम और पहल शामिल हैं।

3- समाधान@75

- विशिष्ट लक्ष्यों और लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ करना।
- यह विषय हमारी मातृभूमि के भाग्य को आकार देने के हमारे सामूहिक संकल्प और दृढ़ संकल्प पर केंद्रित है।
- 2047 की यात्रा के लिए हममें से प्रत्येक को जागृत होना होगा और व्यक्तियों, समूहों, नागरिक समाज, शासन संस्थानों आदि के रूप में अपनी भूमिका निभानी होगी।
- हमारे सामूहिक संकल्प, सुनियोजित कार्य योजनाओं और दृढ़ प्रयासों से ही विचार कार्यों में परिणत होंगे।
- इस विषय के तहत कार्यक्रमों में संविधान दिवस, सुशासन सप्ताह आदि जैसी पहल शामिल हैं, जो उद्देश्य की दृढ़ भावना से प्रेरित होकर श्पृथ्वी ग्रह और उसके लोगोंश के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को जीवंत करने में मदद करती हैं।

आजादी का अमृत महोत्सव

हैं और सामूहिक रूप से एक बेहतर कल बनाने में हमारी मदद करती हैं।

- इस विषय के तहत कार्यक्रमों में गति शक्ति - मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान जैसी पहल शामिल हैं।

4. एक्शन@75

- नीतियों को लागू करने और प्रतिबद्धताओं को साकार करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डालना।
- यह विषय उन सभी प्रयासों पर केंद्रित है जो भारत को कोविड के बाद की दुनिया में उभरती नई विश्व व्यवस्था में नीतियों को लागू करने और प्रतिबद्धताओं को साकार करने के लिए उठाए जा रहे कदमों को उजागर करने में मदद करने के लिए किए जा रहे हैं।
- यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के प्रधान मंत्री मोदी के आह्वान से प्रेरित है।
- इसमें सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्य योजनाओं के साथ-साथ व्यवसायों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज की प्रतिबद्धताएं शामिल हैं जो हमारे विचारों को साकार करने में मदद करती

5. उपलब्धिया@75

- विभिन्न क्षेत्रों में विकास और प्रगति को प्रदर्शित करना।
- यह विषय समय बीतने और रास्ते में हमारे सभी उपलब्धियों को चिह्नित करने पर केंद्रित है।
- इसका उद्देश्य 5000+ वर्षों के प्राचीन इतिहास की विरासत के साथ 75 साल पुराने स्वतंत्र देश के रूप में हमारी सामूहिक उपलब्धियों के सार्वजनिक अकाउंट के रूप में विकसित होना है।
- इस विषय के तहत कार्यक्रमों में 1971 की जीत के लिए समर्पित स्वर्णिम विजय वर्ष, महापरिनिर्वाण दिवस के दौरान श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ आदि जैसी पहल शामिल हैं।

डिजिलॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) की एक प्रमुख पहल है। डिजिलॉकर का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुँच प्रदान करके नागरिकों का 'डिजिटल सशक्तिकरण' करना है। 8 फरवरी, 2017 के नोटिस जी.एस.आर. 711 (ई) के जरिये सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर सुविधाएं प्रदान करने वाले बिचौलियों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण) नियम, 2016 के नियम 9ए के अनुसार डिजिलॉकर सिस्टम में जारी किए गए दस्तावेजों को मूल भौतिक दस्तावेजों के बराबर माना जाता है।

1 नागरिकों के लिए लाभ

- महत्वपूर्ण दस्तावेज कभी भी, कहीं भी!
- प्रामाणिक दस्तावेज, कानूनी रूप से मूल के बराबर।
- नागरिक की सहमति से डिजिटल दस्तावेज का आदान-प्रदान।
- तेजी से सेवा वितरण- सरकारी लाभ, रोजगार, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य।

2 एजेंसियों को लाभ

- **प्रशासनिक कार्य कम किया:** यह कागज रहित शासन की अवधारणा के उद्देश्य से कागज के उपयोग तथा सत्यापन प्रक्रिया को कम करके प्रशासनिक कार्य में लगने वाले समय को कम करता है।
- **डिजिटल परिवर्तन:** विश्वसनीय जारी (इशुड) दस्तावेज प्रदान करता है। डिजिलॉकर के माध्यम से उपलब्ध जारी(इशुड) दस्तावेज को उसी समय सीधे जारीकर्ता एजेंसी से प्राप्त किया जाता है।
- **सुरक्षित दस्तावेज गेटवे:** नागरिक की सहमति से विश्वसनीय जारीकर्ता और विश्वसनीय अनुरोधकर्ता/सत्यापनकर्ता के बीच भुगतान गेटवे जैसे सुरक्षित दस्तावेज विनिमय(एक्सचेंज) प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।
- **रियल टाइम वेरिफिकेशन :** एक सत्यापन मॉड्यूल प्रदान करता है जो सरकारी एजेंसियों को यूजर की सहमति प्राप्त करने के बाद सीधे जारीकर्ताओं से डेटा सत्यापित करने में सक्षम बनाता है।

3 डिजिलॉकर के प्रमुख घटक

- **होम** - यह आपके डिजिलॉकर अकाउंट की होम स्क्रीन है, जहां से आप डिजिलॉकर के अन्य खण्डों पर जा सकते हैं। यह जारी किए गए दस्तावेजों का सारांश और डिजिलॉकर के साथ एकीकृत भागीदारों से दस्तावेज प्राप्त करने के लिए एक लिंक भी दिखाता है।
- **जारी किए गए दस्तावेज** - यह खंड डिजिलॉकर के साथ एकीकृत सरकारी विभाग या एजेंसियों द्वारा जारी किए गए डिजिटल दस्तावेजों या प्रमाणपत्रों के यूआरआई (लिंक) की सूची दिखाता है। ।
- **डिजिलॉकर ड्राइव** - यह खंड आपके द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों को दिखाता है। यहाँ आप दस्तावेज प्रकार को अपडेट कर सकते हैं और इन अपलोड किए गए दस्तावेजों को साझा कर सकते हैं।
- **गतिविधि** - यह खंड डिजिलॉकर अकाउंट में आपके द्वारा की गई सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखता है। रिकॉर्ड में फाइल अपलोड, डाउनलोड, शेयर आदि जैसी गतिविधियों के बारे में विवरण शामिल होता है।
- **दस्तावेज देखें (ब्राउज करें)** - यह खंड डिजिलॉकर के साथ पंजीकृत/रजिस्टर जारीकर्ता के विभागों और एजेंसियों की सूची प्रदान करता है। । यदि इन विभागों ने आपको कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र जारी किया है, तो यह आपके जारी दस्तावेज खंड में एक यूआरआई (लिंक) के रूप में दिखाई देगा।

डिजिलॉकर

4 डिजिलॉकर में लागू सुरक्षा विशेषताएं

- आईएसओ (**ISO**) 27001 प्रमाणित डेटा सेंटर: एप्लिकेशन को आईएसओ (ISO) 27001 सुरक्षा प्रमाणित डेटा केंद्र पर होस्ट किया गया है।
- **डेटा बैकअप:** डेटा का बैकअप सुरक्षित वातावरण में उचित ढंग के साथ लिया जाता है।
- **टाइम्ड लॉग आउट:** नागरिकों के अकाउंट को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए, विस्तारित निष्क्रियता का पता चलने पर हमारा सिस्टम सत्र को स्वचालित रूप से समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- **सुरक्षा ऑडिट:** मान्यता प्राप्त ऑडिट एजेंसियों द्वारा डिजिलॉकर को ऑडिट किया जाता है और समय-समय ओअर एप्लिकेशन सुरक्षा ऑडिट प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाते हैं।
- **यूजर सहमति आधारित सिस्टम:** डिजिलॉकर के डेटा को केवल नागरिक की स्पष्ट सहमति से ही साझा किया जाता है। जिन संगठनों को नागरिकों के प्रमाणपत्रों तक पहुंच की आवश्यकता है, उन्हें डिजिलॉकर पर पंजीकरण करना होगा और नागरिकों से स्पष्ट सहमति लेनी होगी।

डिजिलॉकर का उपयोग करना पूरी तरह से कुशल और सुरक्षित है। डेटा सुरक्षा हेतु निम्न उपाय किये गए हैं :

- **मानक तरीके:** डिजिलॉकर तय कोडिंग मानकों, दिशानिर्देशों और समीक्षाओं के मानक सॉफ्टवेयर विकास प्रथाओं का पालन करता है। हमारे सर्वर पर डाले जाने से पहले प्रत्येक रिलीज की समीक्षा की जाती है और सुरक्षा और पैठ बनाने की कमियों के लिए आंतरिक रूप से उनका परीक्षण किया जाता है।
- 256 बिट **SSL** एन्क्रिप्शन: डिजिलॉकर किसी भी गतिविधि के दौरान प्रेषित जानकारी के लिए 256 बिट सुरक्षित सॉकेट लेयर (एसएसएल) एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है।
- **मोबाइल प्रमाणीकरण आधारित साइन अप:** डिजिलॉकर यूजरओं को प्रमाणित करने और प्लेटफॉर्म तक पहुंच की अनुमति देने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से मोबाइल प्रमाणीकरण आधारित साइनअप का उपयोग करता है।

एक पेशे के रूप में सेक्सवर्क

1. खबरों में क्यों

सेक्स वर्क को एक "पेशे" के रूप में मान्यता देते हुए, सेक्स-वर्कर्स को कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा का हकदार बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पुलिस को वयस्क और सहमति देने वाले यौनकर्मियों के खिलाफ न तो हस्तक्षेप करना चाहिए और न ही आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए।

2. सेक्स वर्कर के बारे में

सेक्सवर्कर्स वयस्क होते हैं एवं सहमति से यौन सेवाओं या प्रदर्शनों के बदले नियमित रूप से या कभी-कभी पैसे या सामान प्राप्त करते हैं।

3. सेक्स वर्क और मानव तस्करी के बीच अंतर

- मानव तस्करी एक घोर मानवाधिकार उल्लंघन है जिसमें शोषण के उद्देश्य के लिए धमकी या बल प्रयोग, अपहरण, धोखे या अन्य प्रकार के जबरदस्ती शामिल हैं। इसमें जबरन श्रम, यौन शोषण, गुलामी, और अन्य शामिल हो सकते हैं।
- सेक्स वर्क वयस्कों के बीच एक सहमति से किया जाने वाला लेन-देन है, जहां यौन सेवाओं को बेचने या खरीदने का कार्य मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।

4. न्यायाधीश का निर्णय

"इस देश में प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी भी पेशे में लगा हुआ है, को संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत एक सम्मानजनक जीवन का अधिकार है," अदालत ने कहा।

- यौनकर्मी कानून के समान संरक्षण की हकदार हैं। आपराधिक कानून सभी मामलों में 'आयु' और 'सहमति' के आधार पर समान रूप से लागू होना चाहिए। जब यह स्पष्ट हो जाए कि यौनकर्मी वयस्क है और सहमति से भाग ले रही है, तो पुलिस को हस्तक्षेप करने या कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए।
- बेंच ने आदेश दिया कि जब भी किसी वेश्यालय पर छापा मारा जाए तो यौनकर्मियों को षगिरफ्तार या दंडित या परेशान या पीड़ितष नहीं किया जाना चाहिए, ष्चूंकि स्वैच्छिक सेक्स वर्क अवैध नहीं है और केवल वेश्यालय चलाना गैरकानूनी हैष।
- यौनकर्मियों द्वारा उठाए गए उपाय, जैसे कंडोम का इस्तेमाल, पुलिस को अपने "अपराध" के सबूत के रूप में नहीं लेना चाहिए।

5. बच्चों और नाबालिगों के बारे में

- यदि यौनकर्मी दावा करती है कि बच्चा/अवयस्क उसका बेटा/बेटी है, तो यह निधारित करने के लिए परीक्षण किए जा सकते हैं कि क्या दावा सही है और यदि ऐसा है, तो नाबालिग को जबरन अलग नहीं किया जाना चाहिए।
- सेक्स वर्कर के बच्चे को केवल इस आधार पर मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए कि वह देह व्यापार में है।
- "मानव शालीनता और गरिमा की बुनियादी सुरक्षा यौनकर्मियों और उनके बच्चों तक को उपलब्ध है," अदालत ने कहा।
- यदि कोई नाबालिग वेश्यालय में या यौनकर्मियों के साथ रहता पाया जाता है, तो यह नहीं माना जाना चाहिए कि बच्चे का अवैध व्यापार किया गया था।

6. संविधान की छाया

- पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का प्रयोग किया।
- पीठ ने अपने फैसले में अनुच्छेद 21 को भी लागू किया।

7. मेडिको-लीगल केयर

- अदालत ने पुलिस को आपराधिक शिकायत दर्ज कराने वाली यौनकर्मियों के साथ भेदभाव नहीं करने का आदेश दिया, खासकर अगर उनके खिलाफ किया गया अपराध यौन प्रकृति का है।
- यौन उत्पीड़न की शिकार यौनकर्मियों को तत्काल चिकित्सा-कानूनी देखभाल सहित हर सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
- अदालत ने पुलिस को यौनकर्मियों के प्रति संवेदनशील होने का आदेश दिया ।

8. मीडिया के लिए विशेष निर्देश

- मीडिया को इस बात का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए कि गिरफ्तारी, छापे और बचाव कार्यों के दौरान यौनकर्मियों की पहचान उजागर न करें, चाहे वह पीड़ित हों या आरोपी हों और ऐसी कोई भी तस्वीर प्रकाशित या प्रसारित न करें जिससे ऐसी पहचान का खुलासा हो।
- न्यायालय ने दृश्यावलोकन को एक आपराधिक अपराध होने की बात याद दिलाई है ।

इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए रोडमैप

नीति आयोग ने जून 2021 में 'भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए रोडमैप 2020-25' पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार :

(i) 2025-26 तक इथेनॉल के उत्पादन और आपूर्ति के लिए एक वार्षिक रोडमैप।

(ii) इथेनॉल के देशव्यापी विपणन के लिए सिस्टम ।

जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 को जून 2018 में अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य 2030 तक पेट्रोल में इथेनॉल के 20% सम्मिश्रण को प्राप्त करना था। दिसंबर 2020 में, इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा को संशोधित कर 2025 कर दिया गया था।

मुख्य अवलोकन और सिफारिशें:

1 इथेनॉल मांग-अनुमान :

- रिपोर्ट का अनुमान है कि पेट्रोल मिश्रण के लिए भारत की इथेनॉल की आवश्यकता 2019-20 में 173 करोड़ लीटर से बढ़कर 2025-26 में 1,016 करोड़ लीटर हो जाएगी।
- इस मांग को पूरा करने के लिए इथेनॉल उत्पादन क्षमता को 2019-20 में 684 करोड़ लीटर से बढ़ाकर 2025-26 में 1,500 करोड़ लीटर करना होगा।
- इसमें निम्नलिखित उत्पादन क्षमता शामिल है:

> 740 करोड़ लीटर अनाज आधारित इथेनॉल।

> 760 करोड़ चीनी आधारित इथेनॉल।

- भारत भर में रोल आउट को सक्षम करने के लिए, आवश्यकता के आधार पर, सरप्लस राज्यों से कम उत्पादन वाले राज्यों को इथेनॉल की आपूर्ति की जा सकती है।

2 इथेनॉल सम्मिश्रण रोडमैप:

रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अप्रैल 2022 तक E10 ईंधन (10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल का मिश्रण) की उपलब्धता के लिए एक योजना को अधिसूचित करना चाहिए ।

- मंत्रालय को पुराने वाहनों के लिए ईंधन की निरंतर उपलब्धता के लिए एक योजना अधिसूचित करनी चाहिए।
- 2025 तक E20 की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल 2023 से 20% इथेनॉल (E20) के साथ मिश्रित ईंधन को चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जाना चाहिए।

3 नियामकीय मंजूरी में तेजी :

- इथेनॉल उत्पादन संयंत्रों को नई परियोजनाओं और मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार के लिए पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होती है।
- रिपोर्ट इथेनॉल उत्पादन के लिए नियामक मंजूरी में तेजी लाने के लिए कुछ उपायों की सिफारिश करती है जैसे राज्य सरकारों द्वारा डिस्टिलरी स्थापित करने के लिए मंजूरी देने के मामलों में तेजी लाना।
- त्वरित मंजूरी प्रदान करने के लिए डीपीआईआईटी द्वारा एकल खिड़की प्रणाली तैयार की जा सकती है।
- इससे एथेनॉल उत्पादन के लिए नई परियोजनाओं और मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार के लिए त्वरित मंजूरी दी जा सकेगी ।

4 इथेनॉल मूल्य निर्धारण और पर्यावरणीय प्रभाव:

- 2018-19 में, सरकार ने एक अलग मूल्य निधारण नीति पेश की, जिसमें चीनी मिलों को बी-हैवी मोलासेस और गन्ने के रस से इथेनॉल उत्पादन के लिए उच्च दरों की पेशकश की गई थी।
- यह गन्ना आधारित इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करता है।
- चीनी से एक लीटर एथेनॉल के लिए लगभग 2,860 लीटर पानी की आवश्यकता होती है।
- रिपोर्ट जल संरक्षण के लिए, निम्न प्रोत्साहनों का सुझाव देता है

> कम पानी वाली फसलों से इथेनॉल का उत्पादन ।

> मक्का और दूसरी पीढ़ी के स्रोतों से उत्पादन को बढ़ावा देना।

5 इथेनॉल अनुकूल वाहन:

- उच्च इथेनॉल मिश्रणों का उपयोग करने के लिए, इंजन की विफलता को रोकने के लिए वाहनों को समग्र रूप से डिजाइन करने की आवश्यकता है।
- फ्लेक्स फ्यूल वाहनों की कीमत सामान्य पेट्रोल वाहनों की तुलना में अधिक होगी।
- भविष्य में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल अनुकूल वाहनों का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए, समिति ने निम्न सिफारिश की:

> E20 मटेरियल कंप्लेंट और E10 इंजन ट्यून्ड वाहन, अप्रैल 2023 से पूरे देश में शुरू किए जा सकते हैं।

> E20 ट्यून इंजन वाले वाहनों को अप्रैल 2025 से रोल आउट किया जा सकता है।

6 डी-नेचरड इथेनॉल का अप्रतिबंधित संचलन:

- रिपोर्ट में कहा गया है कि सम्मिश्रण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इथेनॉल डी-नेचरड इथेनॉल है।
- राज्य सरकारों को मानव उपभोग के लिए शराब पर कानून बनाने, नियंत्रण करने और कर और शुल्क लगाने का अधिकार है।
- रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि पूरे भारत में डी-नेचरड इथेनॉल की आवाजाही राज्यों के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए।
- पूरे भारत में अप्रतिबंधित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए इसे केवल केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।

5 मई की मध्यरात्रि के समय, नासा के अंतरिक्ष थर्मामीटर म्ब्ब्ज्त्ै ने दिल्ली के उत्तर-पश्चिम में 12.350 वर्ग किमी की एक पिक्चर ली । इसने शहरी और ग्रामीण इलाकों में रात के समय के तापमान में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर दिखाया।

1. अर्बन हीट आइलैंड के बारे में

- एक अर्बन हीट आइलैंड (यूएचआ. ई) तब होता है जब कोई शहर आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म तापमान का अनुभव करता है।
- तापमान में अंतर आमतौर पर रात के दौरान और हवा के कमजोर होने पर देखा जाता है। यूएचआई तब देखा जाता है जब गर्मी और सर्दी दोनों मौसम अपने चरम पर होते हैं।
- आमतौर पर अर्बन हीट आइलैंड का औसत तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 8 से 10 डिग्री अधिक होता है।

2. यूएचआई के कारण

- निर्माण सामग्री: शहरों के विस्तार के लिए आवश्यक डामर और कंक्रीट, भारी मात्रा में गर्मी को अवशोषित करते हैं तथा शहरी क्षेत्रों के औसत सतह-तापमान में वृद्धि करते हैं।
- शहरी वास्तुकला: अक्सर संकरी सड़कों में स्थित ऊंची इमारतें, हवा के संचलन में बाधा डालती हैं, हवा की गति को कम करती हैं, और इस प्रकार किसी भी प्राकृतिक शीतलन प्रभाव को कम करती हैं। इसे अर्बन कैन्यन इफेक्ट कहते हैं।
- काली सतहें: शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली कई इमारतों में गहरे रंग की सतह होती है, जिससे एल्बीडो कम होता है और गर्मी का अवशोषण बढ़ जाता है।
- एयर कंडीशनिंग: अंधेरे सतहों वाली इमारतें अधिक तेजी से गर्म होती हैं और एयर कंडीशनिंग से अधिक शीतलन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए बिजलीसंयंत्रों से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे अधिक प्रदूषण होता है। एयर कंडीशनर आगे स्थानीय तापन का कारण बनते हैं।
- सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की आवश्यकता: परिवहन प्रणाली और जीवाश्म ईंधन का अबाधित उपयोग भी शहरी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ाता है।
- पेड़ों की कटाई और हरे क्षेत्रों को कम करना: यह वाष्पीकरण, छाया और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में बाधा डालता है, ये सभी प्रक्रियाएं आसपास की हवा को ठंडा करने में मदद करती हैं।

3. यूएचआई का प्रभाव

- ऊर्जा लागत: शहरी हीट आइलैंड प्रभाव ऊर्जा लागत, वायु प्रदूषण के स्तर और गर्मी से संबंधित बीमारी और मृत्यु दर को बढ़ाता है।
- ग्लोबल वार्मिंग: कूलिंग के लिए एयर-कंडीशनिंग की बढ़ती खपत ग्लो. बल वार्मिंग में योगदान करती है, जो आगे चलकर जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है।
- खराब वायु गुणवत्ता: यूएचआई में अक्सर हवा की गुणवत्ता कम होती है क्योंकि हवा में अधिक प्रदूषकों को मिलाया जाता है। इन प्रदूषकों को शहरी भवन, सड़कें, फुटपाथ और पार्किंग स्थल द्वारा बिखरने और कम विषाक्त बनने से रोक दिया गया है ।
- पानी की खराब गुणवत्ता: पानी की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। जब यूएचआई से गर्म पानी स्थानीय धाराओं में बहता है, तो यह उन देशी प्रजातियों को प्रभावित करता है जो ठंडे जलीय वातावरण में जीवन के लिए अनुकूलित हो गई हैं।
- गर्म वातावरण में रहने वाली प्रजातियों द्वारा औपनिवेशीकरण: शहरी क्षेत्रों में उच्च तापमान के कारण, यूएचआई उन प्रजातियों के उपनिवेशण को बढ़ाता है जो गर्म तापमान पसंद करती हैं, जैसे कि छिपकली और जेकॉस।
- हीटवेव्स: शहरों में हीटवेव्स का अनुभव होता है जो मानव और पशु स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जिससे गर्मी में ऐंठन, नींद की कमी और मृत्यु दर में वृद्धि होती है।

परिदृश्य:

अर्बन हीट आइलैंड

4. अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव को कम करने के उपाय

- पेड़ और अन्य वनस्पतियां लगाएं- शहरी क्षेत्रों में जगह सीमित हो सकती है, लेकिन छोटे हरित बुनियादी ढांचे को आसानी से एकीकृत किया जा सकता है।
- जहां कहीं भी संभव हो, देशी, सूखा-सहिष्णु छायादार पेड़ और छोटे पौधे जैसे कि झाड़ियाँ, घास और जमीन पर लगाकर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाना ।
- हरे रंग की छतें बनाएं- हरे रंग की छतें एक हीट आइलैंड में कमी हेतु आदर्श रणनी. ति है, जो प्रत्यक्ष और परिवेशीय शीतलन प्रभाव दोनों प्रदान करती है।
- इसके अलावा, हरी छतें हीट आइलैंड प्रभाव को कम करके और प्रदूषकों को अवशोषित करके वायु गुणवत्ता में सुधार करती हैं।

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 मई 2022 को टोक्यो, जापान में दूसरे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें जापान के प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीज शामिल थे।

क्वाड के सिद्धांत:

- क्वाड के पीछे का मकसद हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सामरिक समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना है।
- क्वाड का मुख्य उद्देश्य एक नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था, नेविगेशन की स्वतंत्रता और एक उदार व्यापार प्रणाली को सुरक्षित एवं सुनिश्चित करना है।
- गठबंधन का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए वैकल्पिक ऋण वित्तपोषण की व्यवस्था करना भी है।
- समसामयिक वैश्विक मुद्दों जैसे महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत, जलवायु परिवर्तन, महामारी और शिक्षा पर विचारों का आदान-प्रदान करना ।

चारों नेताओं ने निम्नलिखित घोषणाएं की:-

1. शांति और स्थिरता

- यूक्रेन में चल रहे युद्ध और मानवीय संकट पर चर्चा की गई।
- क्वाड एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक के लिए प्रतिबद्ध है।
- आसियान एकता और केंद्रीयता के लिए समर्थन भी दिखाया गया।
- तंरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनस. ीएलओएस), और नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता के रखरखाव के लिए समर्थन।
- आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की गई।

2 COVID-19 और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा

- क्वाड देशों ने वायरस को नियंत्रित करने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया है, जिसमें नए रूपों की तैयारी, और सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों के लिए टीके, परीक्षण, उपचार और अन्य चिकित्सा उत्पाद उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

क्वाड

8 अंतरिक्ष

- जलवायु परिवर्तन, आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया, और महासागरों तथा समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग जैसी चुनौतियों के लिए अंतरिक्ष से संबंधित अनुप्रयोग और प्रौद्योगिकियां।
- अर्थ ऑब्जरवेशन सेटेलाइट डेटा और अनुप्रयोगों के लिए सार्वजनिक पहुंच में सुधार करना।
- अर्थ ऑब्जरवेशन आधारित निगरानी

9 समुद्री डोमेन जागरूकता और एचएडीआर

- समुद्री डोमेन जागरूकता के लिए इंडो-पैसिफिक पार्टनरशिप (आईप. ीएमडीए)
- यह मानवीय और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और अवैध रूप से मछली पकड़ने से निपटने के लिए क्षेत्रीय भागीदारों के साथ काम करेगा।

3 बुनियादी ढांचा

- नेता बुनियादी ढांचे पर सहयोग को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता और समृद्धि को बढाने के लिए महत्वपूर्ण है।
- नेताओं ने ऋण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की, जो कई देशों में महामारी से बढ़ गए हैं।
- "क्वाड डेट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल" की भी घोषणा की गई, जो क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करेगा।

4 जलवायु

- इसके दो विषयों के रूप में "शमनW और ''अनुकूलन'' के साथ ''क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज (क्यू-चैंप Q-CHAMP)" भी लॉन्च किया गया था।
- क्यू-चैंप में शामिल हैं :

a) साझा ग्रीन कॉरिडोर ढांचे के उद्देश्य से ग्रीन शिपिंग और पोर्ट।

b) प्राकृतिक गैस क्षेत्र से स्वच्छ हाइड्रोजन और मीथेन उत्सर्जन में स्वच्छ ऊर्जा सहयोग।

c) स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाना।

d) प्रशांत महासागरीय द्वीप देशों के लिए जलवायु सूचना सेवाएं।

5 साइबर सुरक्षा

- क्वाड साइबर सुरक्षा साझेदारी के तहत हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
- साइबर खतरों से खुद को बेहतर ढंग से बचाने के लिए जागरूक करने हेतु पहला क्वाड साइबर सुरक्षा दिवस।

6 महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकियां

- 5G और 5G से आगे की प्रौद्योगिकियों, क्वांटम प्रौद्योगिकियों पर घनिष्ट सहयोग ।
- वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना।

7 क्वाड

- एसटीईएम क्षेत्रों में स्नातक डिग्री हासिल करने के लिए हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्ययन करने के लिए 100 छात्रों के लिए क्वाड फैलोशिप।

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न

1. निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए :

राज्य	जल संभरण तकनीकें
A. मध्य भारत	1. जोहाद
B. पश्चिमी घाट	2. सुरंगम
C. पूर्वी घाट	3. कोरम्बु
D. लद्दाख	4. जिंग

कूट :

	A	B	C	D
(a)	2	1	3	4
(b)	1	2	3	4
(c)	3	4	1	2
(d)	1	4	2	3

2. एक पारितंत्र के दोनों प्रकार्यात्मक और संरचनात्मक विशेषताओं के पोषणीय अंतर्संबंधों का प्रदर्शन कहलाता है –
(a) खाद्य शृंखला
(b) खाद्य जाल
(c) खाद्य पिरामिड
(d) पोषण स्तर

3. मैक्रोन्यूट्रिएन्ट्स तत्वों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए :
1. कैल्सियम
2. सोडियम
3. मैग्नीशियम
4. लोहा
5. फास्फोरस
6. सल्फर

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :
(a) केवल 1, 2, 3 और 4
(b) केवल 2, 5 और 6
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3, 5 और 6

4. निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए :

घास के मैदान	अवस्थिति
A. वेल्ड	1. दक्षिण अफ्रीका
B. पुस्ताज	2. हंगरी
C. पम्पास	3. सोवियत संघ
D. स्टेपीज	4. अर्जेंटीना
E. प्रेयरीज	5. उत्तरी अमेरिका

कूट :

	A	B	C	D	E
(a)	2	3	5	1	4
(b)	1	2	5	3	4
(c)	2	5	1	3	4
(d)	1	2	4	3	5

5. प्रजातियां, जो किसी विशेष क्षेत्र में पहले ही विलुप्त हो गई हों, कहलाती हैं –
(a) एंडेंजर्ड स्पीशीज
(b) एक्सटिंक्ट स्पीशीज
(c) वल्नरेबल स्पीशीज
(d) रेयर स्पीशीज

6. ध्वनि प्रदूषण को रोकने में सहायक नियमों के बारे में विचार कीजिए :
1 फैक्टरी अधिनियम, 1948
2. औद्योगिक अधिनियम, 1951
3. मोटरवाहन अधिनियम, 1939
4. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 3 और 4
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 1, 2, 3 और 4

7. निम्नलिखित गैसों में से कौन-सी गैस विषाक्त नहीं है?
(a) नाइट्रस ऑक्साइड
(b) सल्फर डाईऑक्साइड
(c) हाइड्रोजन डाईऑक्साइड
(d) कार्बन मोनो ऑक्साइड

8. 'ज्वारीय ऊर्जा' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. यह असमाप्य और ऊर्जा की सस्ती स्रोत है।
2. भारत ने विजिंगम मत्स्यन बंदरगाह (तिरूअनंतपुरम्) में तरंग ऊर्जा कार्यक्रम शुरू किया है।
3. इसका विकास नीदरलैण्ड की सहायता से किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौनसे कथन सही हैं ?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3
(d) केवल 1 और 3

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अभी हाल ही में, मध्य प्रदेश सरकार ने पक्षियों पर अंतर्राष्ट्रीय पर्व की शुरूआत की है।
2. अपने तरह के इस पहले पर्व का आयोजन राष्ट्रीय चम्बल

अभ्यारण्य (एनसीएस) में सम्पन्न हुआ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2

10. निम्नलिखित राज्यों में से कौन-सा राज्य भारत का पहला 'प्लास्टिक बैग मुक्त' राज्य बना?
(a) अरुणाचल प्रदेश
(b) मध्य प्रदेश
(c) सिक्किम
(d) राजस्थान

11. जिका वायरस के कारण होने वाले जिका बुखार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जिका वायरस दिन में सक्रिय एड्ज मच्छरों द्वारा फैलता है।
2. जिका बुखार का प्राय: कोई लक्षण नहीं प्रकट होता है अथवा बहुत मामूली लक्षण प्रकट होता है जो डेंगू बुखार के लक्षणों की भाँति होता है।
3. इसका नाम युगाण्डा के जिका नदी से लिया गया है, जहाँ इस वायरस की पहली बार पहचान हुई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2
(d) 1, 2 और 3

12. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें -
1. भारतीय वन सर्वेक्षण, पूर्व वन संसाधन निवेश सर्वे के स्थान पर प्रारंभ किया गया था।
2. यह एफएओ और यूएनडीपी द्वारा प्रायोजित था।
3. राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एक राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण संगठन के गठन की सिफारिश की।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं ?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) उपर्युक्त सभी

13 मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कौन-कौन सी हैं?
1. अत्यधिक लवणता
2. उच्च ज्वारक्षेत्र
3. तीव्र वायु प्रवाह
4. उच्च तापमान
5. गंदली अवायवीय मिट्टी

नम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए।
(a) केवल 1, 3 और 5
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 2, 4 और 5
(d) उपर्युक्त सभी

14. निम्नलिखित में से कौन-कौन घातक पदार्थ प्रबंधन से संबंधित सम्मेलन हैं?
1. बेसल सम्मेलन
2. रॉटरडम सम्मेलन
3. स्टॉकहोम सम्मेलन
4. मिनीमाता सम्मेलन

निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए।
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) उपर्युक्त सभी

15. रामसर सम्मेलन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन को शामिल करता है?
1. नदियों
2. झीलें
3. लैगून
4. मैंग्रोव
5. दलदली भूमि
6. प्रवाल भित्तियाँ

निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए।
(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 4, 5 और 6
(c) केवल 1 और 2
(d) उपर्युक्त सभी

16. पारिस्थितिकी तंत्र अनुसंधान कार्यक्रम निम्नलिखित में से किन पर लागू है?
1. पूर्वी घाट
2. पश्चिमी घाट
3. मैंग्रोव
4. प्रवाल भित्ति
5. जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र

निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए।
(a)केवल 1 और 2

(b) केवल 3 और 4
(c) केवल 5
(d) उपर्युक्त सभी

17. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का एक वैज्ञानिक मंत्रालय के रूप में प्रादुर्भाव कब हुआ ?
(a) 1985
(b) 1986
(c) 1987
(d) 1988

18. निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित निकाय के प्रायोजक हैं?
1. केन्द्रीय सरकार
2. राज्य सरकार
3. निजी क्षेत्र
निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए।
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) उपर्युक्त सभी

19. राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान कब शुरू हुआ ?
(a) 1986
(b) 1996
(c) 2006
(d) 2015

20. प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ अवस्थित है?
(a) जबलपुर
(b) कच्छ
(c) दिल्ली
(d) कोलकाता

21. जैव विविधता संपन्न क्षेत्र हैं-
(a) उष्णकटिबंधीय क्षेत्र
(b) ध्रुवीय क्षेत्र
(c) शीतोष्ण क्षेत्र
(d) महासागर

22. पर्यावरणीय स्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र मौजूद हैं, जहां पर अनेकों पौधों एवं जानवरों की प्रजातियों को विकास के माध्यम से अनुकूलित किया गया है। इस घटना को किस रूप में जाना जाता है-
(a) पारिस्थितिकीय उत्तराधिकार
(b) पारिस्थितिकीय अनुकूलन
(c) पारिस्थितिकीय विकास
(d) जैव भू-रासायनिक अनुकूलन

23. 'पारिस्थितिक संतुलन'-
(a) एक निवास स्थान में जीवों के एक समुदाय के भीतर गतिशील संतुलन की स्थिति है।
(b) नई प्रजाति, प्राकृतिक खतरों या मानवीय कारणों के प्रवेश से अशान्त हो सकता है।
(c) विभिन्न जीवों के बीच प्रतिस्पर्द्धा एवं सहयोग के माध्यम से घटित होता है, जहां पर आबादी स्थिर रहती है।
(d) उपर्युक्त सभी

24. निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल में शामिल है:
(a) केवल पौधे
(b) सभी सजीव एवं निर्जीव
(c) केवल जानवर
(d) सभी जीवित जीव

25. निम्नलिखित में से कौन-सा/से उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है?
1. ग्रेट सैंडी डेजर्ट
2. पैटागोनिया डेजर्ट
3. गोबी डेजर्ट
4. कालाहारी डेजर्ट
निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) 1 और 3
(b) 2 और 4
(c) 1 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

1	B	11	C	21	C
2	C	12	D	22	A
3	D	13	D	23	B
4	D	14	D	24	D
5	B	15	D	25	D
6	D	16	D		
7	C	17	D		
8	A	18	A		
9	B	19	A		
10	C	20	A		

समसामायिक आधारित बहुविकल्पी प्रश्न

1. हाल ही में उच्च शिक्षा थिंक-टैंक क्यूएस क्वाक्वेरेली साइमंड्स ने 'क्यूएसवर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2022' जारी की है। इस रैंकिंग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें।
   1. कला और मानविकी क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को 188वां स्थान मिला है।
   2. इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को पहला स्थान मिला है।
   3. इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे 56वां स्थान मिला है।

   उपरोक्त कथनों में कौन कौन से सही हैं? कूटों का प्रयोग कर सही विकल्प चुने।
   (a) कथन 1 और 3 (b) कथन 1 और 2
   (c) कथन 2 और 3 (d) तीनों सही हैं
   उत्तर : **a**

2. हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक "द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर" किसकस द्वारा लिखी गयी है?
   (a) शशी थरूर (b) रस्किन बांड
   (c) अमर मित्र (d) जुम्पा लाहिरी
   उत्तर : **c**

3. ओ.हेनरी पुरूस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है?
   (a) सामजिक क्षेत्र में अथक योगदान के लिए
   (b) उत्कृष्ट लघु कथा के लिए
   (c) गणित के क्षेत्र में किये गए काम के लिए
   (d) विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए
   उत्तर : **b**

4. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सेमीकंडक्टर मिशन के लिए एक 17 सदस्यीय समित का गठन किया है इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
   (a) राजीव चंद्रशेखर (b) गजेन्द्र सिंह शेखावत
   (c) अमिताभ कान्त (d) अश्विनी वैष्णव
   उत्तर : **d**

5. ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
   (a) यह रिपोर्ट वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा निकली जाती है।
   (b) रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्तमान समय में पवन ऊर्जा की कुल क्षमता बढ़कर 1000 गीगावॉट हो गई है।
   (c) रिपोर्ट में यह भी बतया गया है कि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में पवन स्थापना क्षमता में कमी आई है।
   (d) 2021 में भारत ने 1.45 ळॅ पवन क्षमता जोड़ी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30% अधिक है।
   उत्तर : **b**

6. फोर्टिफाइड चावल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें।
   1. कैबिनेट ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल वितरित करने को मंजूरी दे दी है।
   2. फोर्टिफाइड चावल को एकीकृत बाल विकास सेवाओं, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण-पीएम पोषण और अन्य कल्याण योजनाओं के माध्यम से भी वितरित किया जाएगा।
   3. चावल के फोर्टिफिकेशन की कुल लागत केंद्र वहन करेगा।

   उपरोक्त कथनों में कौन कौन से सही हैं? कूटों का प्रयोग कर सही विकल्प चुने।
   (a) कथन 1 और 3 (b) कथन 1 और 2
   (c) कथन 2 और 3 (d) तीनों सही हैं
   उत्तर : **d**

7. हाल ही में किस भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2022 दिया गया है?
   (a) गीतांजलीश्री (b) शशि देशपांडे
   (c) अनीता देसाई (d) जुम्पा लाहिरी
   उत्तर : **a**

8. सेमीकंडक्टर मिशन के सन्दर्भ में निम्न कथन पर विचार करें
   1. यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है।
   2. इस सम्बन्ध में गठित समिति की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।
   3. समिति स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए एक इकोसिस्टम विकसित करने के लिए सुझाव देगी।

   कौन सा / से कथन सत्य है / हैं ? कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें।
   (a) केवल 1 तथा 2 (b) केवल 1 तथा 3
   (c) केवल 2 तथा 3 (d) 1,2 तथा 3
   उत्तर : **b**

9. सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट(एसएफडीआर) बूस्टर के परीक्षण के सन्दर्भ में निम्न कथनो पर विचार करें
   1. इसका परीक्षण ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज,

चांदीपुर में किया गया है।

2. इस तकनीक का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संसथान द्वारा किया गया है।

कौन सा / से कथन असत्य है / हैं ? कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें।

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 तथा 2 (d) न तो 1 न 2

उत्तर : **d**

10. पिनाका एमके-W (उन्नत) रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डेनियल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किस संस्था के द्वारा किया गया है -

(a) डीआरडीओ
(b) इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड
(c) आईएसआरओ
(d) म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड

उत्तर : **a**

11. हाल ही में कार्बन कैप्चर के लिए हाइब्रिड सामग्री और प्रक्रिया की डिजाइनिंग की गई है। इस सन्दर्भ में निम्न कथनो पर विचार करें

1. यह अनुसन्धान मिशन इन्नोवेशन के द्वारा किया गया है।
2. यह अनुसन्धान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी (आईआईसीटी), हैदराबाद के द्वारा किया गया है।

कौन सा / से कथन सत्य है / हैं ? कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें।

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 तथा 2 (d) न तो 1 न 2

उत्तर : **c**

12. थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट के सन्दर्भ में निम्न कथनो पर विचार करें

1. इसमें भारत को 3 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं।
2. भारत को कुल 10 पदक प्राप्त हुए हैं।

कौन सा / से कथन सत्य है / हैं ? कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें।

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 तथा 2 (d) न तो 1 न 2

उत्तर : **c**

13. निम्न पुस्तकों में से कौन सा / से विनोद राय द्वारा

1. "नॉट जस्ट ए नाइटवॉचमैन: माई इनिंग्स विद बीसीसीआई"
2. "नॉट जस्ट ए अकाउंटेंट: द डायरी ऑफ द नेशन्स कॉन्शियस कीपर"
3. "रीथिंकिंग गुड गवर्नेंस: होल्डिंग टू अकाउंट इंडियाज पब्लिक इंस्टीट्यूशंस"

कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें।

(a) केवल 1 तथा 2 (b) केवल 1 तथा 3
(c) केवल 2 तथा 3 (d) 1,2 तथा 3

उत्तर : **d**

14. क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के सन्दर्भ में निम्न कथनो पर विचार करें

1. ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने कला और मानविकी स्ट्रीम में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
2. इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे भारत का सबसे बेहतर संस्थान रहा है।

कौन सा / से कथन सत्य है / हैं ? कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें।

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 तथा 2 (d) न तो 1 न 2

उत्तर : **c**

15. नाटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी के खिलाफ यूरोप के हितों की रक्षा के लिए किया गया था।
2. इसकी सदस्यता इसके गठन के बाद से स्थिर बनी हुई है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर : **d**

16. बायोमटेरियल पुलुलान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बायोमटेरियल का उपयोग घावों को कीटाणुरहित करने और उपचार की प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया जा सकता है।
2. सामग्री एक वायरस द्वारा स्रावित होती है और एक एक्सोपॉलीसेकेराइड है।
3. सामग्री का अभी तक कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं हुआ है क्योंकि इसके विषाक्त और प्रतिरक्षा-आनुवंशिक गुण हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, और 3

उत्तर : **b**

Paper IV केस स्टडी

आप एक चिकित्सा अधिकारी हैं और एक अस्पताल की इमर्जेंसी सेवा में तैनात हैं। एक लड़की को इमर्जेंसी वार्ड में भर्ती किया जाता है। लड़की एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुई है और उसकी जान बचाने के लिए तुरंत उसे रक्त प्रदान करने की आवश्यकता है। आप एक समर्पित डॉक्टर हैं और अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं।

लड़की एक ऐसे धार्मिक समुदाय से है जो उसे अपने शरीर में किसी अन्य समुदाय का रक्त लेने से प्रतिबंधित करता है। महिला के साथ उसके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और उसके समुदाय के कुछ नेता आए हुए हैं। ये सब उसे किसी भी तरह से बाहर का रक्त चढ़ाने के विरूद्ध हैं। वो आपको अपनी बात मनवाने के लिए धमकाते हैं और नहीं मानने पर आपको और आपके अस्पताल को बुरे परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे?

कुछ विकल्प आपको दिए हुए हैं। सभी विकल्पों के गुण और अवगुणों का मूल्यांकन कीजिए और अंत में कारणों के साथ बताइए आप इस समस्या को कैसे हल करेंगे?

(i) उसके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से सहमत हो जाएंगे क्योंकि वो जानते हैं बीमार के लिए क्या अच्छा है और बिना रक्त प्रदान किए इलाज का प्रयास करेंगे।

(ii) रोगी को रक्त प्रदान करेंगे, लेकिन ये तथ्य उसके परिवार के सदस्यों से छुपा लेंगे।

(iii) अस्पताल के मुख्य चिकित्सक से सलाह लेंगे और उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे।

(iv) अस्पताल की सुरक्षा की व्यवस्था करने के पश्चात् रक्त चढ़ाएंगे।

उत्तर :

दिए गए मामले में मैं एक चिकित्सक हूँ। मुझे एक घायल लड़की का उपचार करना है जिसे तुरंत रक्त प्रदान करने की आवश्यकता है, परन्तु उसके समुदाय के सदस्य इसके विरूद्ध हैं।

- इस मामले में सत्यनिष्ठा, जिम्मेदारी, करूणा, समानुभूति एवं सेवा-भावना जैसे मूल्य निहित हैं।
- दए गए विकल्पों का मूल्यांकन:

1. परिवार के सदस्यों की माँग को पूरा करने से दुर्घटनाग्रस्त लड़की की जान को खतरा हो सकता है। अत: हम उपचार के साथ समझौता नहीं कर सकते।

2. इस विकल्प में लड़की को तो समुचित उपचार मिल जाएगा परन्तु इस तथ्य को छुपाना नैतिक नहीं है और नजदीक भविष्य में समस्या पैदा कर सकता है।

3 वरिष्ठ चिकित्सक से सलाह लेना अच्छा विकल्प है क्योंकि उसे अधिक अनुभव होगा। लेकिन उसकी सलाह के अनुसार कार्य करना, सलाह और परिस्थिति पर निर्भर करेगा।

4. सुरक्षा की व्यवस्था करना अच्छा विकल्प हो सकता है लेकिन यहाँ प्राथमिकता दुर्घटनाग्रस्त महिला की जान बचाना है। सुरक्षा का इंतजार, उसके जीवन को खतरे में डाल सकता है।

- मेरा विकल्प: लड़की को प्राथमिक उपचार देने के पश्चात मैं तुरंत रक्त प्रदान करने की व्यवस्था करूँगा। लड़की के साथ उसके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और समुदाय के नेता हैं। मैं इन्हें रक्त प्रदान करने के लिए उत्साहित करूँगा क्योंकि ये सभी एक ही समुदाय हैं, इनके रक्त समूह का मिलान करके मैं उपयुक्त रक्तदाता का चयन करूँगा और महिला को रक्त प्रदान करूँगा। यदि इनमें से किसी का भी रक्त नहीं मिला तो नजदीकी रक्त-बैंक से रक्त की व्यवस्था करके महिला की जान बचाऊँगा। तत्पश्चात मैं उसके रिश्तेदारों को इसकी आवश्यकता, जीवन के मूल्य और अपने कर्तव्य के बारे में समझाकर सहमत कर लूँगा। यदि वो फिर भी नहीं माने तो मैं रक्षा प्रहरियों से, उन्हें नियंत्रित करने और पुलिस को बुलाने के लिए कहूँगा।

NOTES

व्यक्ति विशेष : पंडिता रमाबाई

विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 20 मई, 1883 को महाराष्ट्र के भागुर ग्राम (नासिक जिला) में हुआ था। इन्हें वीर सावर. कर के नाम से भी जाना जाता है। सावरकर की शिक्षा देश और विदेश (लंदन) दोनों जगह हुई थी। 1904 में सावर. कर ने पूना में अभिनव भारत सभा की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी (Free India Society) की भी स्थापना की थी। इंडिया हाउस (India House) नामक राष्ट्रवादी संस्था से भी सावरकर जुड़े हुए थे। 1909 में मदन लाल ढींगरा द्वारा लंदन में सर विलियम कर्जन वायली की हत्या की गयी। इस हत्या के तार सावरकर से जोड़े गये क्योंकि अंग्रेजों का कहना था कि हत्या में प्रयोग की गयी पिस्तौल सावरकर ने उपलब्ध करायी थी। अत: उपर्युक्त हत्या, नासिक कलेक्टर जैक्सन की हत्या, इंडिया हाउस संस्था से जुड़े होने इत्यादि के आरोप में विनायक दामोदर सावरकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर अन्डमान-निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेलूलर जेल भेज दिया गया। हालाँकि 1921 में ब्रिटिश सत्ता ने एक समझौते के तहत सावरकर को रिहा कर दिया। इस समझौते में था कि 1937 ई तक राजनीतिक रूप से नजरबन्द रहेंगे और किसी भी प्रकार की राष्ट्रवादी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। सावरकर का निधन स्वतंत्र भारत में 26 फरवरी, 1966 को मुम्बई में हुआ था।

सावरकर का योगदान

विनायक दामोदर सावरकर अपने कई भाषण और लेखों में डॉ भीम. राव अम्बेडकर का उदाहरण देते थे क्योंकि सावरकर, अम्बेडकर के निचले तबके के लोगों के उत्थान और समाज में उनके अन्य योगदान से काफी प्रभावित थे। इसीलिए कई इतिहासकारों का कहना है कि (अम्बेडकर मेहर समुदाय) और सावरकर (ब्राह्मण) दोनों ही जातिवाद के चरम वर्ग (extreme section) से आते थे किन्तु विचारधारा के मामले में दोनों ही राष्ट्रवादी नेता काफी समानताएँ रखते थे।

सावरकर चाहते थे कि तत्कालीन भारतीय समाज में सुधार आये। इसीलिए 1920 में उन्होंने अपने भाई नारायण राव को पत्र लिखा और उसमें कहा कि जितने संघर्ष की आवश्यकता औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध है उतने ही संघर्ष की आवश्यकता जातिगत भेदभाव व छूआछूत के विरुद्ध भी है।

सावरकर अंग्रेजों के 'श्वेत व्यक्ति का बोझ सिद्धान्त' (White Man's Burdenship Theory) के विरुद्ध थे। उन्होंने इतिहास को प्रमाणिक ढंग से लिपिबद्ध किया और भारतीयों में विश्वास जगाने का प्रयास किया अर्थात् उन्होंने भारतीय इतिहास को उजागर किया ताकि जनता अपने अतीत को जाने और उनकी चेतना में जागृति आये। उनका विश्वास था कि जब एकबार जन जागृति आ जायेगी तो अंग्रेजों द्वारा फैलाये जा रहे झूठ का जनता आसानी से सामना कर पायेगी और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग स्वयं प्रशस्त करेगी।

वीर सावरकर धार्मिक रीति-रिवाजों में वैज्ञानिकता के पक्षधर थे। उनका मानना था कि धार्मिक प्रथाओं को वैज्ञानिक सोच व तार्किकता के साथ जरूर देखना चाहिए। सावरकर ऐसे पहले राष्ट्रवादी थे जिन्होंने सर्वप्रथम बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक (1904-05 के आस-पास) में स्वराज की बात की। जबकि कांग्रेस ने काफी समय बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्वराज की बात की। सावरकर एक संयुक्त भारत के पक्षधर थे। वह चाहते थे कि अलग-अलग संस्कृति के लोग मिल-जुलकर रहें और एक ऐसा भारत निर्मित हो जो समावेशी व गतिशील हो। सावरकर ने इस बात पर भी बल दिया था कि हमें यूरोपीय समाज से सीखना चाहिए तथा उनकी तरह प्रौद्योगिकी पर बल प्रदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सावरकर अन्वेषण व नवीन विचारों को भी समर्थन देते थे। सावरकर की भारतीय सिनेमा के प्रति फ्रयूचरिस्टिक एप्रोच (futuristic approach) काफी सराहनीय थी।

सन् 1907 में लंदन में सावरकर ने 1857 की क्रांति की स्वर्ण जयंती मनायी। सावरकर ने अपनी पुस्तक 'इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, 1857' के द्वारा यह स्थापित किया कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश सरकार 1857 की क्रांति को सेना द्वारा एक विद्रोह मानती थी। भारत में राष्ट्रवाद की क्रांति जगाने वालों में सावरकर प्रारम्भिक क्रांतिकारी थे। सावरकर की पुस्तक (इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल) क्रांतिकारियों के लिए एक प्रेरणास्रोत थी।

सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, लेखक, प्रखर चिन्तक, ओजस्वी वक्ता और दूरदर्शी राजनेता थे जिन्होंने भा. रतीयों को हीन भावना से बाहर निकालने में अतुलनीय योगदान दिया।

मध्यकालीन इतिहास की प्रमुख शब्दावलियां

मसनद-ए-हकूमत - राजकीय प्राधिकार या शाही सत्ता।

मवास-किलाबंद गाँव।

मवाजी-गाँव ।

मिहतर-नायक या (गवर्नर) सूबेदार, नाजिम, आदि।

मिल्क-संपत्ति, लेकिन मध्यकालीन युग में इसका अर्थ राज्य द्वारा आवंटित या प्रदत्त भू-राजस्व अर्जन करने वाली भूमि थी।

मिसल-अधीन अथवा राजाज्ञा।

मिस्काल-द्राम और तीन बटा सात (3/7) हिस्से का वजन या बाट।

मीजान-संतुलन अथवा मापकों का जोड़ा (तराजू)।

मीजान-ए-अहन- लोहे का तराजू।

मोहल्ला-नगर का कोई हिस्सा या इलाका।

मुफलिकी माल वा खिदमत-किसी कार्य या सेवा के लिए आवश्यक कुल धन और साज-सामान ।

मुहसिल्लान-कर और पेशकश वसूल करने वाले व्यक्ति ।

मुहस्सिल-एकत्रित या वसूल किया गया कर।

मुहतसिब-नैतिक मूल्यों तथा सार्वजनिक नैतिकता, कानून-व्यवस्था की निगरानी करने वाला अधिकारी।

मुलुकुत तवैफ-जनजातीय राजतंत्र अथवा अव्यवस्थित प्रशासन।

मुंशी- प्रतिबंधित चीजों एवं कार्यों से संबंधित आदेशों को लागू करवाने वाले अधिकारी।

मुक्कद्दम-ग्राम प्रधान (मुखिया)।

मुक्ता-गवर्नर अथवा बड़ी इक्ता का प्रभारी व्यक्ति।

मुरत्तब- सुसज्जित घुड़सवार

मुसादरत-जुर्माना अथवा आर्थिक दंड।

मुशरिफ- लेखाधिकारी।

मुशरिफ-ए-गुमालिक सभी प्रांतों का लेखाधिकारी।

मुशरिफ-ए-मुगालकत समूची सलानत का लेखाधिकारी (महालेखा. कार) ।

मुस्तबिल- (सरकारी) शाही कर्मचारी।

मुस्तौफी-ए-ममालिक-समूची सल्तनत का लेखापरीक्षक।

यरलिंग-शाही फैसला, आदेश या स्वीकृति।

रबी-भारत की शीतकालीन फसलें।

राय-हिंदू मुखिया जिसके पास सामान्यत: अपनी भूमि और सेना होती थी।

राय रायान-रायों का राय राय का खिताब महत्त्वपूर्ण हिंदू शासकों और राजाओं को दिया जाता था।

रैय्यत-प्रजा या कर अथवा राजस्व देने वाली जनता।

रैय्यत परवार-प्रजा की देखभाल।

रकाबखाना-घोड़ों की लगाम और काठी रखने का स्थान।

राणा-हिंदू शासकों या अधीनस्थ शासकों की श्रेणी ।

रतिबी-मनुष्यों और पशुओं को भोजन देना।

रतिबी कारखाना-मनुष्यों और पशुओं की खाद्य आवश्यकताओं का उत्पादन करने वाले

शाही कारखाने ।

रवात-ए-अर्ज-बलबन के युद्धमंत्री इमाद-उल-मुल्क को दिया गया खिताब या उपाधि ।

रायत-ए-आला-शाही मानदंड।

रिस्मन फरोशी-धागे और रस्सियों पर बिक्रीकर ।

रुस्तै- ग्रामीण।

लंगरखाना- लंगर प्रदान करने वाला स्थान; नि:शुल्क भोजन देने वाला रसोईघर।

लाख बख्श-दान में लाखों देने वाला।

ANNUAL SUBSCRIPTION OF PERFECT 7 CURRENT AFFAIRS MAGAZINE (FORTNIGHTLY)

About Perfect 7:

The role of Current Affairs in Civil Services has tremendously increased, in all the subjects of General Studies like Economy, Polity, Science and Technology, International Relations, Environment, etc.

Need: Knowledge of Current Affairs

Inadequate Solution: Monthly Magazines available in the Market.

Why Inadequate?

- All magazines are monthly: This means that you get to know about the event after more than one month and students are unable to match the pace with newspaper and other media.
- Not suitable for Civil Services: Events are not analyzed as these magazines also cater to the one day exams and hence they provide only factual information's.
- Too much to read in one go: A student is suddenly burdened to cover too many events in a short time which leads to stress.

Solution to all the above three issues is PERFECT 7 Magazine by Dhyeya IAS.

- Released Fortnightly: A student is abreast with the current events of the month, near real time.
- Detailed Analysis of every event: Civil Services demands a deeper understanding of events, concepts and its analyses and not just know the event and its date.
- Easy to study: Since the magazine is fortnightly, a student is saved from Information overload and can relate with the newspaper, TV and other media coverages with a profound understanding of the current happenings.

Features of PERFECT 7

Important conditions for an IAS/PCS centered magazine		PERFECT 7	OTHERS
• Fortnightly	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Civil Services Exam centered	Hindi	✓	*
	English	✓	*
• Micro-Analysis of current issues & not a mere compilation of facts	Hindi	✓	*
	English	✓	*
• Brain boosters for important issues	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Multiple choice questions & their solution based on brain boosters	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Case studies with model answers for Ethics	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Explanation of important theories through pictures & graphics.	Hindi	✓	×
	English	✓	×

(* some institutes)

Annual Subscription Fee along with Courier Charges:

Cost of the Magazine:	45 x 24 = Rs 1080
Price After 25% Discount	Rs 810
Courier Charges:	30 X 24 = Rs 720
Total Charges:	**Rs 1530**

Annual Subscription Fee for Student Collecting Magazine form Mukherjee Nagar Centre:

Cost of the Magazine:	45 x 24 = Rs 1080
Price After 25% Discount	Rs 810
Total Charges:	**Rs 810**

BANK ACCOUNT DETAILS

Account Holder:-	**Trueword Publication Private Limited**
Bank A/C -	**50200032675602**
IFSC:-	**HDFC0000609**

Terms and Condition:

1. Fee submitted one will not be refunded or adjusted in any condition.
2. Dhyeya IAS ensures no damage or delay during transit however some unavoidable circumstances are beyond our control. responsibility for the delay in delivery,
3. W put best efforts to make the Magazine reach to the subscribers by 10th & 25th of every month.
4. If due to COVID-19 Pandemic or any unforeseen natural disaster or by an act of God, Dhyeya IAS is not able to print the Magazine then the duration of subscription will be increased to compensate for the same.

AN INTRODUCTION

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

Dhyeya IAS, two decades old institution, was founded by Mr.Vinay Singh and Mr. Q. H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential aspirants realize their dreams which is evident from the success stories of the previous years.

As the nation progresses, the young generations become more conscious and aware about their career options. There is plethora of jobs and one among them is civil services, the most prestigious service in the country, which needs no introduction. It attracts many young minds hailing from almost all spectra of academic disciplines. The popular belief that the examination for this service is only meant for the brilliant lots has become a taboo as it also attracts the hardworking, sincere and disciplined minds. The saying- "In the end passion and hard work can substitute natural talent" holds true. It gives immense power and opportunity for young folks to bring about the positive changes in the society which would bring harmony and development. It inculcates values, moral, ethos and feeling of national integrity.

Quite a large number of students desirous of building a career for themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vastly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move may invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. Classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals' capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything, you can only help him find it within himself.

We feel that despite brilliance and diligence, most of the students are lacking proper guidance and aptitude needed to clear Civil Services Examination. This is why, we at Dhyeya IAS amalgamated the traditional as well as modern approach of teaching by incorporating best educators of the industry ably supported by Academic Associates, Class Notes and printed Study Material, routine as well as surprise Tests. Due to its arduous efforts, Dhyeya IAS is able to carve a niche among all the civil services coaching institutes in India. Access to an institution is as important as the quality of Institution. Our faith in this philosophy made us grow. With 12 Face to Face Centers located in different parts in India, Distance Learning Program , Live Streaming Centers and Residential Academy, we have made truly pan India presence. Ever since the foundation the institute has produced a heavy pool of bureaucrats both at central and state level. Dhyeya IAS not only aims at imparting the content of civil services in best way but also nurturing the aspirants as leaders of tomorrow who have a responsibility of fulfilling the dreams of around 1.4 billion Indians. Dhyeya IAS has guided over 50,000 aspirants with more than 4500 selections in civil services. Our journey is a small contribution for the development of the society and nation by nurturing the potential civil services aspirants.

Considering the toughness of Civil Services Exam, where success rate is a meager 0.1 percent, Dhyeya IAS has continuously produced phenomenal results over the years. Year after Year Dhyeya IAS is being recognized for imparting guidance to civil services aspirants using benchmarked quality practices. On the basis of scalability, innovation, achievements, impact potential our efforts and contribution have been acknowledged and rewarded with Education Excellence Awards by ET NOW, Brands Academy, Times of India, etc. This has enhanced motivation, pride and self-esteem of entire Dhyeya family.

₹ 45

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 I **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 I **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 I **Prayagraj :** II & III Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 I **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 I **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow, UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 I **Lucknow (Alambagh) :** 58/1 , Sector-B Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony , Alambagh Lucknow,, Ph: 7518373333, 7518573333 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 I **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 I **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha -751024, Ph: 9818244644/7656949029

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744